राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 256 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, रविवार,14 मार्च 2021, मूल्य रु. 1.50

केरल सरकार को झटका, विधायकों के खिलाफ केस वापस नहीं होंगे

कोच्चि। केरल विधानसभा चुनाव से पहले विजयन सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। केरल हाई कोर्ट ने 2015 में विधानसभा में हंगामा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में वामदल के छह विधायकों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार ने तिरुअनंतपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। सीजेएम की अदालत ने इन विधायकों के खिलाफ न सिर्फ केस वापस लेने की मांग ठुकरा दी थी, बल्कि सभी से सुनवाई का सामना करने को भी कहा था। आरोपितों में उद्योग मंत्री ईपी जयराजन और उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील भी शामिल हैं। वामपंथी पार्टी तब विपक्ष में थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अगले वित्त वर्ष के लिए सदन में बजट पेश कर रहे थे, तब इन विधायकों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की थी, जिसमें सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था। कोरोना महामारी के खिलाफ साथ आए भारत-अमेरिका, 2022 के अंत तक मिलकर बनाएंगे 100 करोड़ वैक्सीन

बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का एलान किया था। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। निवर्तमान विधानसभा में आठ महिला विधायक हैं और बाकी 132 पुरुष विधायक हैं। 1 जून, 2021 को केरल सरकार का कार्यकाल समाप्त होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा ने बताया केरल में पहले 21,498 चुनाव केंद्र थे, अब यहां चुनाव केंद्रों की संख्या 40,771 होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा ने बताया कि केरल में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। राज्य की 140 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। 2 मई को मतगणना होगी।

चुनावी बंगाल में पीएम का पीछा करेंगे किसान?

बोले टिकैत- वो तो हेलीकॉप्टर में चलेंगे, हम पीछे-पीछे ट्रैक्टर में चलेंगे

कोलकाता। कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चार महीने पहले से चल रहा विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है। जहां भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ज्यादातर नेता अब किसानों के प्रदर्शनों को नजरअंदाज कर चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं किसान आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वे बंगाल में जीत का सपना देख रही भाजपा की राह मुश्किल करने के लिए 5 अप्रैल को किसानों को ट्रैक्टर के साथ लेकर राज्य पहुंचेंगे।

राकेश टिकैत को 'द टेलिग्राफ' अखबार से हुई बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, वो तो हेलिकॉप्टर में चलेगा, हम पीछे-पीछे ट्रैक्टर में चलेंगे। टिकैत ने बताया कि उनकी भाजपा के खिलाफ अब बंगाल में लड़ाई है। अब जरूरत है कि हम वहां

● सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने भाजपा पर ''देश कुछ कॉरपोरेटों को बेचने'' की कोशिश करने का आरोप लगाया और लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग सावधानीपूर्वक करने का आग्रह किया। किसानों के आंदोलन को ''अपमानित''करने के लिए केंद्र की निंदा करते हुए पाटकर ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश शासकों ने भी ऐसे कृत्यों का सहारा नहीं लिया जैसा वर्तमान सरकार कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने का स्वागत किया।

रुकें। मैं 5 अप्रैल को बंगाल ट्रैक्टरों के साथ पहुंचुंगा, ताकि गरीबों को दर्द देने के लिए भाजपा की हार सुनिश्चित की जा सके। टिकैत ने कहा कि हम लोगों से अपील करेंगे कि वे जिस पार्टी को चाहें उसे वोट दें, पर भाजपा को नहीं। भाजपा को वोट देना राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने की भाजपा को वोट न देने की अपील- बता दें कि भाकियू किसानों के संयुक्त मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा है, जो कि लगातार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहा है। मोर्चा ने शुक्रवार को ही कोलकाता में एक रैली आयोजित की। एसकेएम ने किसानों से अपील की है कि वे भाजपा को चार राज्य बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश- पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में हराएं। हालांकि, मोर्चा ने यह भी साफ किया है कि भाजपा का विरोध करने के दौरान वह किसी एक पार्टी के लिए अभियान नहीं करेगी।

इससे पहले विभिन्न किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के किसानों और अन्य लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने का अनुरोध किया। मोर्चा ने कहा कि चुनावी हार केंद्र की भाजपा नीत सरकार को तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करेगी।

योगेंद्र यादव-मेधा पाटकर साध चुके हैं भाजपा पर निशाना- एसकेएम नेता योगेंद्र यादव ने संवाददाताओं से कहा, हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं या लोगों से यह नहीं कर रहे हैं वे किसे वोट दें लेकिन हमारी एकमात्र अपील है कि भाजपा को सबक सिखाया जाए। एसकेएम ने एक पत्र भी जारी किया जिसमें राज्य के किसानों से भाजपा को वोट नहीं देने का आग्रह किया गया है। मोर्चा ने पत्र में कहा कि चुनाव में हार से केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर होगी।

सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने भाजपा पर ''देश कुछ कॉरपोरेटों को बेचने'' की कोशिश करने का आरोप लगाया और लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग सावधानीपूर्वक करने का आग्रह किया। किसानों के आंदोलन को ''अपमानित''करने के लिए केंद्र की निंदा करते हुए पाटकर ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश शासकों ने भी ऐसे कृत्यों का सहारा नहीं लिया जैसा वर्तमान सरकार कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने का स्वागत किया।

सरकार किनारे अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों का सर्वे करा रहा जीडीए

योगी सरकार ने दिया है ये आदेश

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थालों को हटाने के सख्त आदेश के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने सभी जोनल आधिकारियों को धार्मिक स्थलों को लेकर रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। सभी से सप्ताह भर के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है।

गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों को लेकर सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर रिपोर्ट तलब किया है। जिसके बाद जीडीए के उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने सभी जोनल अधिकारियों से साथ बैठक की। उन्होंने सभी जोन के अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा है। रिपोर्ट में दर्ज होगा कि धार्मिक स्थल किस विभाग की सड़क पर है। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और जीडीए की सड़कों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को चिह्नित किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि एक जनवरी 2011 अथवा उसके बाद कराया गया है तो उसे तत्काल हटाया जाए। एक जनवरी 2011 से पूर्व कराए गए ऐसे निर्माणों को योजना बनाकर संबंधित धार्मिक संरचना के अनुयायियों अथवा उसका प्रबंधन कर रहे लोगों की ओर से प्रस्तावित निजी भूमि पर छह माह के भीतर स्थानान्तरित कराया जाए।

शहर में अतिक्रमण कर बने हैं कई धार्मिक स्थल

नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण कर शहर की सड़कों के इर्दगिर्द 100 से अधिक धार्मिक स्थल वजूद में हैं। इनमें से अधिकतर 10 वर्ष से ज्यादा पहले के बने हैं। प्राधिकरण हाल के दिनों में सड़क पर नये धार्मिक स्थल के निर्माण को रोकने को लेकर संजीदा रहा है। देवरिया बाईपास, पार्क रोड, पादरी बाजार, जेल बाईपास, बिछिया कैंप और सोनौली रोड पर कई धार्मिक स्थल अतिक्रमण कर बने हुए हैं।

शासन के निर्देश के क्रम में सभी जोनल अधिकारियों को धार्मिक स्थलों को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट आने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। जैसा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आशीष कुमार, उपाध्यक्ष, जीडीए

सड़क हादसे में दो महिलाओं सहित पांच की मौत

जोधपुर। जिले के बाप थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में दो महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं तीन पुरुष, तीन महिलाएं व छह बच्चे घायल हो गए। दिल्ली के पर्यटकों की मिनी बस जैसलमेर से वापस लौटते समय सुबह गाडना गांव के समीप एक ट्रोले से जा टकराई। सभी घायलों को बाप अस्पताल लाया गया है। हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना प्रकट की है।

जैसलमेर-बीकानेर हाइवे पर शनिवार सुबह सात बजे एक मिनी बस और ट्रोले में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रोला पलट गया। वहीं, मिनी बस के परखच्चे उड़ गए। बस में दिल्ली के कुछ लोग जैसलमेर यात्रा के पश्चात वापस दिल्ली लौट रहे थे। बस में सवार सभी लोग अंदर ही फंस गए। मौके पर क्षेत्र के लोगों ने राहत कार्य शुरू कर पुलिस को सूचना दी। दो महिलाएं व तीन पुरुष मिनी

बस के अंदर बुरी तरह से फंस गए। उनकी वहीं पर मौत हो गई। जबकि छह बच्चे, तीन पुरुष व तीन महिलाओं को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बड़ी मुश्किल से बस से बाहर निकलवाया और अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंभीर घायलों को बीकानेर भेजा जा रहा है। पुलिस का मानना है कि मिनी बस व ट्रोले में से किसी एक चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना प्रकट की है।

सुपौल में पति-पत्नी और बच्चों समेत परिवार के 5 लोगों ने संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर की खुदकुशी

सुपौल। बिहार के सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर। जिले में एक ही परिवार के पांच लोगों ने संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी वार्ड चार में रहने वाले पति-पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा एक ही कमरे में फंदे से लटके हुए मिले। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खुदकुशी को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि एक ही परिवार के पांच लोंगों की सनसनीखेज खुदकुशी करने के मामले में अबतक कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है वहीं मुताबिक घटना खुदकुशी है या कुछ और ये जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट

खुदकुशी को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि एक ही परिवार के पांच लोंगों की सनसनीखेज खुदकुशी करने के मामले में अबतक कारणों का पता नहीं चल पाया है।

फोरेंसिंक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचने वाली है। पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। घटना के विस्तृत सूचना का इंतजार किया जा रहा है।

आकाश से आ रही एक और आफत, 21 मार्च को धरती के करीब से गुजरेगा विशाल एस्टेरॉयड

नई दिल्ली। एक मील चौड़ा क्षुद्रग्रह मार्च में पृथ्वी से होकर गुजरेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से जानकारी दी गई है कि इस महीने 21 मार्च को एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। धरती से टकराने की किसी संभावनाओं को वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये क्षुद्रग्रह हमारे ग्रह से करीब 12.5 लाख मील की दूरी से गुजरेगा। माना जा रहा है कि आकार में यह क्षुद्रग्रह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी दोगुना है।

नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार, इस क्षुद्रग्रह को 2001 FO32 नाम दिया गया है। इसे दो दशक पहले खोजा गया था। एजेंसी की ओर से बताया गया कि इस क्षुद्रग्रह की परिधि तीन हजार फीट है और 77,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। आमतौर पर अधिकांश क्षुद्रग्रह इसी रफ्तार से आते हैं।

विशालकाय आकार

● बुर्ज खलीफा	-2720 फीट
● शंघाई टावर	-2073 फीट
● '2010एनवाई65'	-1017 फीट
● स्टैच्यु ऑफ लिबर्टी	-310 फीट
● कुतुब मीनार	-240 फीट

सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के निदेशक, पॉल चोडस के मुताबिक जितनी दूरी से क्षुद्रग्रह गुजरने वाला है वह दूरी चंद्रमा से धरती की दूरी के लगभग 5.25 गुना है। नासा के वैज्ञानिक लांस बैनर की मानें तो 20 साल पहले खोजे गए इस क्षुद्रग्रह के बारे में फिलहाल बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पृथ्वी के नजदीक से गुजरने से हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका जरूर मिलेगा।

दूरबीन से देख सकेंगे: दक्षिणी क्षितिज के थोड़ा ऊपर की ओर 21 मार्च को सूर्यास्त के ठीक बाद इसे आठ इंच के एपर्चर टेलीस्कोप के माध्यम से देखना संभव होगा। बता दें कि इस क्षुद्रग्रह को पहली बार न्यू मैक्सिको में साल 2001 में खोजा गया था।

क्या होता है क्षुद्रग्रह

-सूर्य के इर्दगिर्द चक्कर लगाने वाले छोटे खगोलीय पिंड 'क्षुद्रग्रह' कहलाते हैं। ये मुख्यत- मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद 'एस्टेरॉयड बेल्ट' में पाए जाते हैं। हालांकि, कई बार पृथ्वी के करीब से गुजरने के कारण इनसे अच्छा खासा नुकसान भी संभव है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आगा खान पैलेस, पुणे में आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

नई दिल्ली । पुणे का ऐतिहासिक आगा खान पैलेस जहां भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरुआत के बाद महात्मा गांधी को नजरबंद कर दिया गया था, आज हमारे शानदार स्वतंत्रता संघर्ष और आजादी के बाद देश की उल्लेखनीय यात्रा से प्रेरित होने के लिए सब का आह्वान कर रहा हैढ्ढ भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और स्वाधीनता के संघर्ष में उनके योगदान की जानकारी देने के लिए इस पैलेस में एक सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया हैढ्ढ यह प्रदर्शनी आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच कम्युनिकेशन द्वारा लगाई गई यह प्रदर्शनी 15 मार्च, 2021 तक चलेगीढ्ढ इसमें लगाए गए पैनल्स में स्वतंत्रता संग्राम के महारथियों के योगदान की झलकियाँ हैंढ्ढ स्वतन्त्रता संग्राम की इन विभूतियों में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, लोकमान्य तिलक, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर और कई अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं।

वर्चुअल रूप में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि, ÷असंख्य बलिदानों के बाद हमें स्वतंत्रता मिली हैढ्ढ इसलिए यह आवश्यक है कि हर किसी को स्वतंत्रता संघर्ष की यात्रा के बारे में जानना चाहिए। ये प्रदर्शनियां देशभर में लगाई जा रही हैं ताकि अपने देशवासियों को हमारे शानदार स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के बारे में जानकारी दी जा सके।

मंत्री जी ने आगे कहा आजादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य स्वतंत्र भारत की विभिन्न उपलब्धियों को प्रदर्शित करना भी

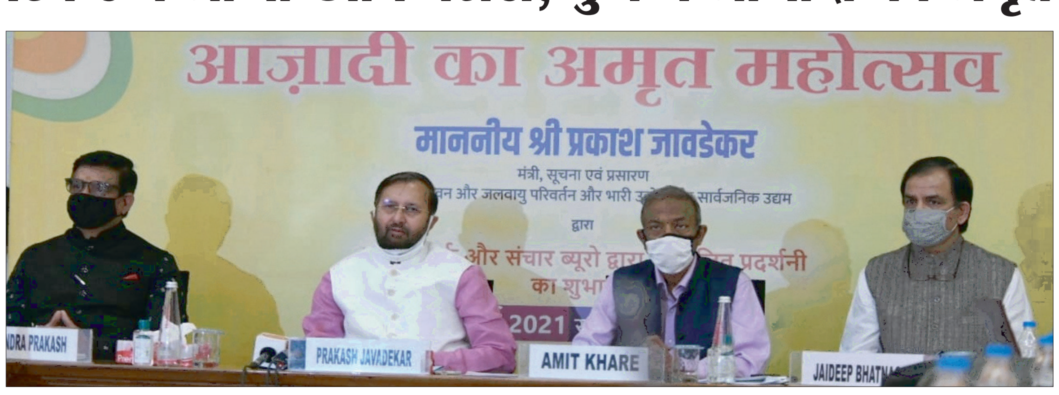

है। हम यह भी चाहते हैं कि सुराज्य की हमारी धारणा के अनुरूप एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में जीवन के सभी क्षेत्रों में अगले 25 वर्षों में देश की प्रगति की कल्पना कर सकें।

नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावडेकर इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर पांच अन्य स्थानों- बेंगलुरु, भुबनेश्वर, पटना, सांबा (जम्मू-कश्मीर) और मोइरांग(मणिपुर) में भी इस प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया।

सूचना प्रसारण मंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि वे इन प्रदर्शनियों में आकर अपने साथ इतिहास का एक अंश ले जाएं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच कम्युनिकेशन द्वारा लगाई गई ये प्रदर्शनियां लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगी और अगले आने वाले 25 वर्षों के लिए दूरदर्शिता के साथ योजना बनाने में सहायक होंगीढ्ढ उन्होंने कहा मैं लोगों को आमंत्रित करता हूं कि वे इन प्रदर्शनियों में आएं और अपने साथ उस इतिहास को संजोकर ले जाएं।

इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने कहा कि इन प्रदर्शनियों का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना और इस लड़ाई में उनके योगदान को याद रखना है। साथ ही इनका उद्देश्य स्वत्रंतता की इस यात्रा में देश के विभिन्न भागों से शामिल हुए गुमनाम नायकों और वीरों के योगदान को भी सामने लाना है ।

प्रदर्शनी के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय निदेशक श्री प्रकाश माडगम ने पुणे के सभी निवासियों, विशेषकर युवकों का स्वागत किया और कहा कि वे इस प्रदर्शनी में आएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरणा लें।

आगा खान महल (पैलेस) का हमारे देश के स्वतंत्रता आदोलन में विशेष महत्व है। यही वह स्थान है जहां 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को 21 महीने के लिए नजरबंद कर दिया थाढ्ढ यह स्थान 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का केंद्र बिंदु बन गया था।अब यह एक संग्रहालय है जिसमें गांधी जी की 21 महीनों की हिरासत (नजरबंदी) की पूरी गाथा दर्शायी गई है।

ऐसी ही प्रदर्शनियां सेवाग्राम, वर्धा और मुंबई में भी लगाई जाएंगी जहां से भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता की प्लेटिनम जयंती मनाने के लिए भारत सरकार अगले 75 सप्ताहों में राज्य सरकारों और विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।

भारत के बढ़ते कद का अंदाजा होने पर साथ चलने को मजबूर पाकिस्तान, सार्क सम्मेलन कराने को तैयार

इस्लामाबाद। दुनिया में भारत के बढ़ते कद का अंदाजा पाकिस्तान को हो गया है। इसीलिए वह अब रास्ता रोकने की नहीं बल्कि साथ चलने की नीति पर कार्य कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) की लंबित बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 2016 में उड़ी में भारतीय सेना के ठिकाने पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में होने वाली सार्क की बैठक में शामिल न होने की घोषणा कर दी थी। भारत का रुख देखकर बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी बैठक में शामिल होने से इन्कार कर दिया था।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा, पाकिस्तान सार्क के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस रास्ते में आने वाली कृत्रिम रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। सार्क की आखिरी बैठक 2014 में काठमांडू में हुई थी। 2016 में बैठक इस्लामाबाद में होनी थी लेकिन उड़ी में आतंकी हमले के बाद वह नहीं हो सकी। सार्क के सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक दो साल में एक बार होती है और एल्फाबेट तरीके से यह सदस्य देश में आयोजित होती है। जो देश मेजबानी करता है, वही बैठक की अध्यक्षता भी करता है।

आठ देशों के इस संगठन में भारत और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और भूटान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में सार्क की कार्यसूची को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया है। पहला सार्क सम्मेलन आठ दिसंबर, 1985 को ढाका में हुआ था। आठवें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान 2007 में संगठन से जुड़ा है।

मीडिया से बातचीत में पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारत से कोविड से बचाव की वैक्सीन के आयात से इन्कार किया। कहा कि वैक्सीन खरीद का कोई समझौता दोनों देशों के बीच नहीं हुआ है। चौधरी ने बताया कि वैक्सीन के लिए बने अंतरराष्ट्रीय गठबंधन गावी ने पाकिस्तान के समक्ष वैक्सीन लेने का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान गावी से वैक्सीन लेने पर विचार कर सकता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री बोले, अफगानिस्तान से सेना वापसी पर अभी नहीं लिया गया कोई निर्णय

वाशिंगटन। हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान से सेना की वापसी को लेकर अब अमेरिका के सुर बदल गए हैं। विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान से अभी अमेरिका की सेना वापसी पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तालिबान से हुए अमेरिकी समझौते में एक मई तक सेना की वापसी की डेडलाइन तय की गई थी। ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बाइडन प्रशासन इसकी समीक्षा कर रहा है।

किसी भी समीक्षा से पहले नहीं व्यक्त करना चाहते अपनी राय

ब्लिंकन ने संसद की विदेशी मामलों की समिति के सामने कहा कि वह किसी भी समीक्षा से पहले अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। हालांकि अभी तक सेना के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में वार्ता के बाद शांति के लिए स्थाई समझौता हो जाए, जिससे सभी पक्ष अपने समझौते का पालन कर सकें। हमने अपने प्रयासों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र व सभी संबंधित देशों से प्रयास करने के लिए कहा है।ज्ञात हो कि रविवार को अमेरिका के अफगानिस्तान में शांति के लिए नियुक्त विशेष दूत जालमे खलीलजाद की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी सभी पहलुओं पर वार्ता हुई थी।

भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने श्रीलंका के पर्यटन मंत्री के साथ तीर्थ यात्रियों के लिए भवन निर्माण की रखी आधारशिला

कोलंबो। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने वहां के पर्यटन मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा के साथ तीर्थयात्रियों के आवास के लिए भवन निर्माण की आधारशिला रखी। नेशनल लेडी ऑफ मधु स्थित परिसर में तीर्थयात्रियों के लिए 144 पारगमन आवास इकाइयों (यूनिट) का निर्माण किया जाएगा। इन इकाइयों को भारत से अनुदान सहायता के साथ बनाया जाएगा।इसके साथ ही श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने राम सेतु का भी दौरा किया और महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना भी की। उच्चायुक्त बागले महाशिवरात्रि के खास मौके पर भारत और लंका के बीच बने राम सेतु पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत और श्री लंका के लोगों के बीच मजबूत संबंध स्थापित हों इसकी प्रार्थन की।इस यात्रा के कुछ ही घंटे बाद भारतीय उच्चायुक्त ने लंका के उत्तरी प्रांत के थिरुकीतेस्वरम मंदिर का दौरा किया और यहां भी शिवरात्रि की पूजा में भाग लिया।

बता दें कि नेशनल लेडी ऑफ मधु स्थान ईसाईयों का यह प्रमुख पूजा स्थल है, जो कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 300 किलोमीटर दूर इंगिनियागला क्षेत्र में स्थित है। भारत से ईसाई धर्म के लोग यहां बड़ी संख्या में जाते हैं।

मिस्र में कपड़ा फैक्ट्री में आग, 20 लोगों की मौत, 24 घायल

राजधानी काहिरा के पास ओबौर में हुआ हादसा

काहिरा। अफ्रीकी देश मिस्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। हादसा राजधानी काहिरा के पास ओबौर में हुआ। मौके पर पहुंचे आग बुझाने वाले 15 वाहनों के जरिए आग को बुझाया गया। चार मंजिला संयंत्र में आग लगी। इससे लोग फंस गए। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। काहिरा में ही पिछले महीने 13 मंजिला इमारत में आग लग गई थी। इसे बुझाने में एक दिन लग गया था। बाद में इस इमारत को गिरा दिया गया। पिछले साल दिसंबर में ओबौर में ही एक निजी अस्पताल में आग लग गई थी। इसमें सात लोग मारे गए थे। इसी तरह से अलेक्जेंड्रिया में एक अस्पताल इमारत में आग लगने से सात मरीजों की मौत हो गई थी।

महिला महाशक्ति: बाइडेन ने मिलिट्री कमांड्स प्रमुख के लिए 2 महिलाओं के नाम सीनेट को भेजे

वाशिंगटन। अमेरिका में एक और इतिहास बनने वाला है। अभी कुछ महीने पहले ही कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनीं थीं। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलिट्री कमांड्स के प्रमुख के तौर पर दो महिलाओं के नाम सीनेट की मंजूरी के लिए भेजे हैं।

महिला कमांडरों के नाम हैं - जनरल जैकलीन ओवोस्ट और जनरल लॉरा रिचर्डसन। सीनेट की मंजूरी मिलने पर एक ही वक्त पर दो महिलाएं अमेरिकी सेना में बड़े ओहदे संभालेंगी। अभी सिर्फ लोरी रॉबिनसन ने यह कीर्तिमान रचा था। वह 2018 में रिटायर होने तक अमेरिकी सेना की उत्तरी कमान की प्रमुख थीं। अमेरिकी मिलिट्री में सबसे बड़ी रैंक चार

स्टार जनरल की है। इसे वायुसेना की जनरल जैकलीन ओवोस्ट हासिल कर चुकी हैं। जैकलीन 2020 में रक्षा विभाग में इकलौती चार स्टार महिला जनरल बनीं और अमेरिकी वायु सेना के इतिहास में ऐसी पांचवी महिला। उनका नाम ट्रांसपोर्टेशन कमांड प्रमुख के तौर पर दिया गया है। इसी तरह, तीन स्टार जनरल लॉरा रिचर्डसन का नाम दक्षिण कमान की प्रमुख के लिए प्रस्तावित किया गया है।

ट्रम्प के डर से नामों की घोषणा में हुई देरी: रिपोर्ट

अमेरिकी रक्षा मुख्यालय 'पेंटागन' ने पिछले साल ही लॉरा और जैकलीन का नाम तय कर लिया था। लेकिन उनके नाम भेजने में देर होती रही। इसका कारण पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का डर बताया जा रहा है। अमेरिका के पूर्व डिफेंस सचिव मार्क एस्पर को डर था कि ट्रम्प लॉरा और जैकलीन के नाम पर मंजूरी नहीं देंगे। क्योंकि दोनों महिलाएं हैं। हालांकि जो बाइडेन ने अंततः पांच मार्च को दोनों नाम सीनेट को भेज दिए।

अमेरिका में कोरोना का एक साल: राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा-

कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकियों ने कुछ न कुछ खोया, पहले और दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा मौतें हुई

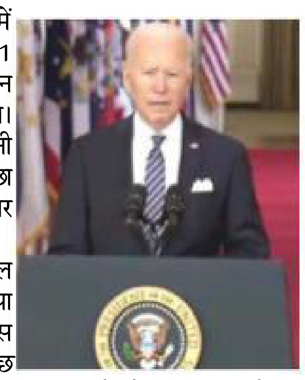

वाशिंगटन। अमेरिका में कोरोना को फैले शुक्रवार को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंधकार में रोशनी खोजना अमेरिका का सबसे अच्छा काम है। वास्तव में यह अधिकतर अमेरिकन का काम हो सकता है।

बाइडेन ने कहा कि एक साल पहले यह वायरस खामोशी से आया और सभी में फैल गया। इस वायरस ने हमें बहुत आघात पहुंचाया। कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों तक हम इसे नजरंदाज करते रहे। लापरवाही से कई मौतें हो गईं। यह सब कुछ अलग था। इस वायरस की वजह से हम सभी ने कुछ न कुछ खो दिया। बाइडेन ने इसे सामूहिक बलिदान बताया।

कोरोना में पहले और दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा मौतें हुईं

बाइडेन ने आगे कहा, मुझे पता है कि यह कठिन है। मेरे पास एक कार्ड है। इसमें अमेरिका में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा है। अब तक अमेरिका में 527,726 मौतें हो चुकी हैं। यह आंकड़ा पहले, दूसरे विश्वयुद्ध, वियतनाम युद्ध और 9/11 से भी ज्यादा है।

19 खरब के राहत पैकेज पर साइन किए

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 खरब के राहत पैकेज पर साइन किए। इस राहत पैकेज को उन्होंने कोरोना की वजह से दिक्कत झेल रहे लोगों के लिए लाभदायक बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना से दिक्कत झेल रहे लोगों, बिजनेसमैन को मदद मिलेगी और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा।

जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को ईयू में मंजूरी, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिलेगा टीका

ब्रसेल्स। यूरोपीय यूनियन (ईयू) के दवा नियामक ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। फाइजर-बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मॉडर्ना के टीकों के बाद यह चौथा टीका है, जिसे यूरोपीय यूनियन के देशों में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह टीका दिया जाएगा। यह पहली सिंगल डोज वैक्सीन है यानी इसकी एक ही खुराक कोरोना संक्रमण से बचाने में सक्षम होगी। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमर कुक ने कहा कि इस मंजूरी से ईयू के देशों में महामारी से लड़ने और अपने लोगों की सेहत की रक्षा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प होगा। ईएमए के बाद यूरोपीय कमीशन ने भी टीके को अंतिम मंजूरी दे दी है। अमेरिका, कनाडा और बहरीन में भी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है।जॉनसन एंड जॉनसन के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर पॉल स्टोफेल्स ने इसे कंपनी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

म्यांमार की सेना का सू की पर आरोप: सेना ने कहा-

सू की ने अवैध तरीके से 4.36 करोड़ रुपए लिए, राष्ट्रपति और कई मंत्री भी घेरे में

नेपितॉ। म्यांमार में सैन्य शासन लगने के बाद पद से हटाई गई स्टेट काउंसलर आंग सान सू की पर सेना ने अवैध तरीके से 4 करोड़ 36 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। उन पर गलत तरीके से सोना लेने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि, इसके कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं। यह भी नहीं बताया गया कि यह रकम किससे और क्यों ली गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 फरवरी को सू की को पद से हटाने के बाद अब सेना ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रिगेडियर जनरल जॉ मिन तुन ने राष्ट्रपति विन माइंट और कई कैबिनेट मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

चुनाव में धोखाधड़ी का दावा

सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेट्स ने पिछले साल हुए चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। सेना चुनाव में धोखाधड़ी किए जाने का दावा करती है। वहीं, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑब्जर्वर सेना के दावे को खारिज करते हुए चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार करते हैं।

5 हफ्ते से सू की कहीं नजरबंद

सू की को पिछले 5 हफ्तों से अज्ञात जगह पर रखा गया है। वे गैरकानूनी रूप से रेडियो उपकरण

रखने और कोविड-19 नियमों को तोड़ने सहित कई आरोपों का सामना कर रही हैं।

सेना के खिलाफ प्रदर्शन में 60 से ज्यादा की मौत

सेना ने म्यांमार के कई शहरों में जारी प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की बात नहीं की है। सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लगातार प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं। वे सैन्य शासकों से म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने की अपील कर रहे हैं। अब तक इन प्रदर्शनों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने 2 हजार से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। गुरुवार को भी विरोध के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई।

भारत से 'कोरोना वैक्सीन' आयात करने पर अभी पाकिस्तान की नहीं कोई योजना

इस्लामाबाद। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अन्य देशों की तरह इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में पिछले दिनों खबर आई थी कि भारत अपने पड़ोसी देश (पाकिस्तान) को फ्री में भारत निर्मित वैक्सीन सप्लाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आए ताजा बयान में यह साफ होता प्रतीत हो रहा है कि वह भारत से वैक्सीन आयात करने के मूड में नहीं है। दरअसल, पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं को बताया कि कोरोना से बचाव के लिए भारत से वैक्सीन आयात करने की पाकिस्तान की अभी कोई योजना नहीं है।

दोनों देशों के बीच नहीं हुआ कोई समझौता

उन्होंने कहा कि अभी दोनों देशों के बीच वैक्सीन खरीद का भी कोई समझौता नहीं हुआ है। चौधरी ने बताया कि वैक्सीन के लिए बने अंतरराष्ट्रीय गठबंधन 'गावी' ने पाकिस्तान के समक्ष वैक्सीन लेने का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान गावी से वैक्सीन लेने पर विचार कर सकता है।

जानें क्या है गावी

बता दें कि GAVI, गावी वैक्सीन से जुड़ा एक एलायंस है, जिसने दुनियाभर के करीब आधे बच्चों को दुर्बल और खतरनाक संक्रामक रोगियों को बचाने के लिए टीकाकरण किया है। महामारी के इस दौर में इस एलायंस ने पाकिस्तान की मदद की है। रिपोर्ट की माने तो इससे पहले सितंबर महीने में पाकिस्तान को वैक्सीन देने पर समझौता हुआ था। माना जा रहा है कि इसके जरिए पाकिस्तान कोरोना वेक्सीन लेने पर विचार कर सकता है।

म्यांमार: जुंटा का अत्याचार जारी, अब तक कई प्रदर्शनकारियों की ले चुका जान

म्मंडालय। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन कर रहे करीब 10 और लोगों की जान ले ली। गत 1 फरवरी को म्यांमार में तख्तापलट के बाद सैन्य शासन की शुरुआत हो गई जिसपर लोग विरोध जता रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तब से लेकर अब तक देश की सेना जुंटा के द्वारा 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों की जान ली जा चुकी है। देश की सैन्य सरकार लोगों के विरोध को दबाने के लिए उनपर गोलियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है और उनपर पानी की बौछारें कर रही है। देश में लगातार हो रहे प्रदर्शन और अब इसके खिलाफ सेना की कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चिंता की जा रही है। इस क्रम मे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों पर हमले की निंदा करता है और अधिक हिंसा होने पर वह कार्रवाई करेगा। बता दें कि विरोध प्रदर्शनों को रोकने के नाम पर सेना ने देशभर में भीड़ पर गोलीबारी की। प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा इस कार्रवाई के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपील किया है कि इस पर रोक लगाया जाए। दरअसल, एक स्वतंत्र ह एक्सपर्ट ने मानवता के खिलाफ बढ़ते अत्याचार का हवाला दिया। इस बीच सेना ने नेता आंग सान सू की पर एक और आरोप लगाया है। सेना का कहना है कि उन्होंने अवैध तरीके से 6 लाख डॉलर यानि लगभग 4 करोड़ 36 लाख रुपये और 11 किलो सोना जमा किया। तख्तापलट के बाद निर्वाचित सरकार को बेदखल कर सेना ने आंग सान सूकी व अन्य वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया था। बता दें कि सू की की पार्टी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पिछले साल नवंबर में होने वाले चुनावों में जीत हासिल हुई थी।

पाकिस्तान सीनेट अध्यक्ष के चुनाव के लिए मारा-मारी, विपक्ष का आरोप आईएसआई के जरिए सांसदों पर डाला जा रहा दबाव

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में शुक्रवार को सीनेट के चेयरमेन और डिप्टी चेयरमेन के लिए चुनाव होना है। इसको लेकर हर पार्टी ने अपनी कमर कस रखी है। एक तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से पाकिसतान पीपुल्स पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को सीनेट के चेयरमेन और जेयूआई-एफ के नेता मौलाना अब्दुल गफूर को डिप्टी चेयरमेन के लिए खड़ा किया गया है वहीं इमरान खान की सत्ताधारी पार्टी पीटीआई ने कार्यकाल खत्म कर रहे चेयरमेन मोहम्मद सादिक संजरानी को ही दोबारा इस पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है।

इनके अलावा प्रधानमंत्री इमरान खान फाटा से अरबपति सांसद मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को डिप्टी चेयरमेन के पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है।

इस हाई प्रोफाइल चुनाव से पहले ही विपक्षी सांसदों ने ये कहते हुए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है कि सरकार की तरफ से सांसदों पर उनके प्रत्याशी को ही चुनने का दबाव डाला जा रहा है। इससे पहले विपक्ष सरकार पर सांसदों की खरीद-फरोख्त का भी आरोप लगा चुका है। इमरान खान ने जिस व्यक्ति को सीनेट के डिप्टी चेयरमेन के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है वो वर्ष 2018 में निर्दलीय के तौर पर चुने गए थे। इसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की गोद में जाकर

सरकार भी इसको अच्छे से जान रही है इसलिए जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सीनेट इसी तरह से काम करती है जैसे भारत में राज्य सभा।

बैठ गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने पीएमएल-एन को तिलांजलि देते हुए पीटीआई का दामन थाम लिया। वहीं सीनेट के चेयरमेन संजरानी की बात करें तो उनके खिलाफ वर्ष 2019 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव तक ला चुका है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन का कहना है कि सीनेट में विपक्ष का पलड़ा भारी है, लेकिन इसके बाद भी सत्ता और विपक्ष के बीच में जोरदार टक्कर है। डॉन का कहना है कि इस चुनाव में जीत के आसार विपक्षी पार्टी के प्रत्याशियों के ही हैं।

सरकार भी इसको अच्छे से जान रही है इसलिए जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सीनेट इसी तरह से काम करती है जैसे भारत में राज्य सभा। सीनेट पाकिस्तान का उच्च सदन है, जिसमें 104 सांसद हैं। यहां पर सांसदों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। मौजूदा सीनेट में होने को तो 100 सदस्य हैं लेकिन इशाक डार जो खुद स्वेच्छा से देश छोड़कर विदेश में रह रहे हैं उन्होंने सदन के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ली है।

इस तरह से मौजूदा सीनेट में पीटीआई के 27, बलूचिस्तान आवामी पार्टी के 12, एमक्यूएम के 3, तीन निर्दलीय, पीएमएल-क्यू और जीडीए के एक-एक, पीपीपी के 21, पीएमएल-एन के 17, जेयूआई-एफ के पांच, एएनपी, बीएनपी-एम, पीकेएमएपी के दो-दो, नेशनल पार्टी और जमात ए इस्लामी के एक-एक, सांसद हैं। इस तरह से विपक्ष के पास 52 सांसद हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी पीटीआई के पास 47 सांसद हैं। जमात ए इस्लामी ने इस चुनाव में हिस्सा न लेने की घोषणा पहले ही कर दी है।

चुनाव से पहले पीएमएल-एन के उपाध्यक्ष शाहिद खक्कान अब्बासी ने देश की सिक्योरिटी एजेंसियों से इस चुनाव के बाबत न्यूट्रल रहने की सलाह दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से सांसदों को फोन कर अपने पक्ष में करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए वो आईएसआई का सहारा ले रही है। सांसदों को एनएबी, एफआईए और एंटी करप्शन के मामनों में फंसाने का डर दिखाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो अधिकारी केवल हुक्म मान रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है।

उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले इस तरह की बातें नहीं सुनी गईं। लेकिन देश में जब से इमरान खान की सरकार सत्ता में आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। अब्बासी ने ये भी कहा कि आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल ने उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि सिक्योरिटी एजेंसियों का इस चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए उनकी इसमें कोई भूमिका भी नहीं होगी।

ISRO ने लांच किया साउंडिंग रॉकेट RH-60, न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा गतिशीलता का करेगा अध्ययन

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र , श्रीहरिकोटा रेंज से साउंडिंग रॉकेट RH-60 को लांच किया है। इसरो इस रॉकेट लांच से न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक भिन्नताओं का अध्ययन करेगा। ISRO ने अपने आधिकारिक अकाउंट ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। इसरो ने लिखा- श्रीहरिकोटा रेंज में तटस्थ हवाओं(न्यूट्रल विंड) और प्लाज्मा डायनामिक्स में एटिट्यूडिनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट लांच किया गया।

इसरो के अनुसार, ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच के लिए और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किए जाने एक या दो चरण वाले ठोस रॉकेट हैं।इसरो ने कहा कि वे लांच किए गए वाहनों और उपग्रहों में उपयोग के लिए नए घटकों या उप-प्रणालियों के प्रोटोटाइप का परीक्षण करने या साबित करने के लिए आसानी से किफायती प्लेटफ़ॉर्म के रूप में भी काम करते हैं। इसरो ने 1965 से स्वदेशी रूप से निर्मित लगने वाले रॉकेट लांच करना शुरू कर दिया था और इसके बाद ठोस प्रणोदक प्रौद्योगिकी में अनुभव के साथ बहुत अधिक माहिर हो गया है।

न्यू स्पेस इंडिया करेगी 10000 करोड़ रुपये का निवेश:भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की व्यावसायिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लि. (एनएसआईएल) ने कहा कि वह कामकाज बढ़ाने के लिए अगले पांच साल में करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस दौरान उसे करीब 300 अतिरिक्त लोगों की भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेश्क जी नारायणन ने बंगलुरू में संवाददाताओं से कहा कि एनएसआईएल इक्विटी और कर्ज के जरिये सालाना 2,000 करोड़ रुपये जुटाएगी।

केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आने वाली कंपनी ने 28 फरवरी को अपनी पहली वाणिज्यिक मिशन की शुरूआत की। इसके तहत ब्राजील का उपग्रह अमेजोनिया-1 को श्रीहरिकोटा से कक्षा में स्थापित किया गया। नारायणन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल से सालाना करीब 2,000 करोड़ रुपये निवेश की जरूरत होगी।

सकारात्मक सोच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें रोगी कल्याण समिति : विधायक

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार की तस्करी में उत्तर प्रदेश (सकारात्मक सोच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें रोगी कल्याण समितिः आप विधायक डाबड़ी स्थित दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में शनिवार को रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) की सलाना अंतिम बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें समिति के नवनिर्वाचित चेयरमेन विधायक विनय मिश्रा व 11 सदस्यों को परिचित किया गया। इस पर दक्षिण-पश्चिमी जिले में एसडीएम हेडक्वार्टर पीयूष मोहंती, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक व आरकेएस के सचिव डा. बृजेश कुमार व अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डा. दीपमाला मौजूद रहीं। बैठक के दौरान डा. बृजेश ने 20 दिसंबर 2020 को आयोजित पिछ्ली बैठक में लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डाला और साथ ही नवनिर्वाचित सदस्यों को आरकेएस की कार्य प्रणाली से भी अवगत किया। साथ आरकेएस फंड से अस्पताल में जारी सुविधाओं का भी वर्णन किया।

बैठक के दौरान आठ विभिन्न श्रेणियों में से एक-एक कर्मचारी को उनके कोरोना काल के दौरान किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। विनय मिश्रा ने कहा कि आरकेएस समाज व अस्पताल प्रशासन के बीच एक बांध की तरह काम करती है। इसलिए सदस्यों को सकारात्मक भावना व सोच के साथ अस्पताल प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ताकि मरीजों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं मिल सकें। दबाव होने के कारण कमियां स्वाभाविक है, पर उन कमियों को दूर करने पर हमे जोर देना है। विनय मिश्रा ने बताया कि उन्हें कई आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से अस्पताल के चिकित्सकों के व्यवहार को लेकर शिकायत मिली है, इस पर अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वे सभी कर्मचारियों को इस बाबत समझाएं। वहीं पीयूष मोहंती ने कहा कि अस्पताल के विकास पर प्रशासन का पूरा ध्यान केंद्रित है और ये जिले का माडल अस्पताल है।

दिल्ली दंगा : दंगे की साजिश रचने के आरोपितों की न्यायिक हिरासत नौ दिन बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली दंगे के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, जेएनयू के छात्र शरजील इमाम, पूर्व पार्षद इशरत जहां, देवांगना कलीता समेत 16 आरोपितों की न्यायिक हिरासत नौ दिन के लिए बढ़ गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते इस मामले में सुनवाई 25 मार्च तक के लिए टाल दी गई है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही जांच

यह मामला गत वर्ष दिल्ली में हुए दंगे की साजिश से जुड़ा है। जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। अब तक इस मामले में एक मुख्य और दो पूरक आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं। पिछ्ली सुनवाई में स्पेशल सेल ने दूसरे पूरक आरोपपत्र को एनिमेशन वीडियो के रूप में दिखाकर कोर्ट को यह बताया था कि साजिशकर्ताओं ने दंगे शुरू कराने से पहले किस तरह से सीसीटीवी कैमरे तोड़े थे। यह भी बताया था कि किन गलियों से होते हुए हथियारों से लैस दंगाई मुख्य वजीराबाद रोड पर पहुंचे थे और पुलिस पर हमला किया था। इस मामले में सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह सुनवाई टल गई। इस मामले में दो आरोपित सफूरा जरगर और फैजान खान जमानत पर हैं। बता दें कि दिल्ली दंगे में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने निर्लंबित कर दिया था।

देश में कोरोना वैक्सीनेशनः हफ्ते में दूसरी बार दिए गए 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज

; राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में भी 25 लाख डोज का आंकड़ा पार

नई दिल्ली। भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण ने महाशिवरात्रि पर आंशिक विश्राम के बाद फिर गति पकड़ ली है। महाशिवरात्रि पर 5 लाख डोज दिए गए थे, वहीं इसके अगले दिन यानी शुक्रवार को चार गुना ज्यादा 20 लाख डोज दिए गए। इसमें भी 11 लाख से अधिक डोज सीनियर सिटीजन को दिए गए। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र ने भी 25 लाख डोज का आंकड़ा पार कर लिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के 13 मार्च सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक वैक्सीन के 2.82 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इनमें भी 2.30 करोड़ पहले डोज और 51.43 लाख दूसरे डोज दिए जा चुके हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि 51 लाख लोग

पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं।

भारत में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था। सबसे पहले हेल्थकेयर वर्कर्स को टीका लगा था। 12 मार्च रात 8 बजे तक हेल्थकेयर वर्कर्स को 72.84 लाख पहले डोज और 41.76 लाख दूसरे डोज दिए जा चुके हैं। फिर 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगना शुरू हुआ। 12 मार्च की रात तक उन्हें 72.15 लाख पहले और 9.28 लाख दूसरे डोज दिए जा चुके हैं।

1 मार्च से सरकार ने सीनियर सिटीजन और 45-59 वर्ष के गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को वैक्सीनेशन में शामिल किया। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को भी टीके लगाने के लिए अधिकृत किया। इसके बाद से आंकड़ों में तेजी आ रही है। शुक्रवार रात तक 71.70 लाख सीनियर सिटीजन को और 12.30 लाख हाई-रिस्क वाले 45-59 वर्ष के लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है।

अमेरिका के बाद सबसे तेज वैक्सीनेशन भारत में

पूरी दुनिया में कई देशों ने भारत से पहले वैक्सीनेशन शुरू किया, इसके बाद भी हमारे यहां ज्यादा वैक्सीन डोज दिए गए हैं। अमेरिका में 9.82 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। वहीं, इसके बाद 2.8 करोड़ डोज के साथ भारत दूसर नंबर पर है। Ourworldindata के मुताबिक अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा डोज रोज दिए जा रहे हैं, जबकि भारत में पिछ्ले हफ्ते में सिर्फ दो बार ही 24 घंटे में दिए गए डोज का आंकड़ा 20 लाख को पार कर सका है। चीन में भी 5 करोड़ डोज दिए जाने का दावा किया जा रहा है, इसकी किसी भी स्तर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, यूके में अब तक 2.5 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं।

दिल्ली, हैदराबाद सहित 9 शहर बनेंगे उच्च शिक्षा के हब, आत्मनिर्भर भारत की मुहिम पर फोकस

नई दिल्ली। देश के प्रमुख शहरों के बीच अब शोध और शिक्षा को लेकर भी प्रतिस्पर्धा दिखेगी। इसकी शुरआत नौ शहरों से होगी। फिलहाल इसके लिए शहरों के चयन का काम तेजी से चल रहा है। जिन शहरों को अब तक इसके उपयुक्त पाया गया है, उनमें दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, जम्मू, बेंगलुर, वाराणसी, पुणे, भुवनेश्वर, जोधपुर और चेन्नई आदि शामिल हैं। हालांकि इनके अंतिम चयन पर अभी मुहर लगनी बाकी है। खास बात यह है कि सरकार इन शहरों को शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकजुट होकर काम करने के लिए अलग से वित्तीय मदद मुहैया कराएगी।

फिलहाल ऐसे शहरों के चयन का जो आधार बनाया गया है, उनमें शोध और उच्च शिक्षण संस्थानों की मौजूदगी के साथ उद्योगों के जुड़ाव को भी देखा जा रहा है। इससे उद्योगों को भी मदद मिल सकेगी। माना जा रहा है कि इनमें चयनित होने वाले शहर

उच्च शिक्षा के एक बड़े हब के रूप में विकसित होंगे। इसका फायदा न सिर्फ देश को मिलेगा बल्कि इन शहरों की ओर से दुनियाभर के छात्रों को आकर्षित किया जा सकेगा। मौजूदा समय में स्टडी इन इंडिया मुहिम के तहत सरकार दूसरे देशों के छात्रों को अपने यहां आकर्षित करने की मुहिम में तेजी से जुटी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद इनमें तेजी भी दिखी है। जिन शहरों को इसके लिए उपयुक्त पाया गया है, उनमें जोधपुर और चेन्नई भी शामिल हैं। शहरों के चयन को लेकर मंत्रलय के स्तर पर अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक इन शहरों के चयन का काम पूरा हो जाएगा।

सरकार ने बजट में ही शोध और उच्च शिक्षण संस्थानों की बाहुल्यता वाले ऐसे नौ शहरों को अलग से वित्तीय मदद देने की घोषणा की थी। इसे ग्लू ग्रांट नाम दिया था। इसका मकसद एक ही शहर में मौजूद दर्जनों संस्थानों द्वारा एकजुट होकर काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना था।

मौजूदा समय में देश में ऐसे दो दर्जन से ज्यादा शहर हैं, जहां मौजूदा समय में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े करीब 40 शोध और उच्च शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। इनमें हैदराबाद भी शामिल है। जहां इस समय 40 से ज्यादा शोध और उच्च शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि अभी ऐसे शहरों में मौजूद इन संस्थानों को अलग-अलग विभागों से वित्तीय मदद दी जाती है और वे अलग-अलग काम करते हैं।

एस जयशंकर ने सीरिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सीरियाई समकक्ष डॉ फैसल मेकड के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। जयशंकर ने बताया, सीरिया के एफएम डॉ फैसल मेकड के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। हमारे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। मानवीय, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण चुनौतियों पर एक साथ काम करने को प्रतिबध।

बताया गया कि भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं और पिछ्ले महीने 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किया था। दोनों देशों ने ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का अच्छा अनुभव लिया है। भारत हमेशा सीरिया के लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा रहा है और कई विकास और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से द्विपक्षीय संघर्ष ने आंतरिक संघर्ष के वर्षों के दौरान भी तेजी से काम करना जारी रखा है।

एक बार फिर डराने लगा है कोरोना, 24 घंटों में 24 हजार से अधिक आए नए मामले

नई दिल्ली। भारत में पिछ्ले 24 घंटे में कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आए और 140 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 13 लाख 33 हजार 7 सौ 28 हो गया और इससे अब तक 1 लाख 58 हजार 4 सौ 46 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या अब 2,02,022 है और संक्रमण से स्वस्थ हुए मामलों की कुल संख्या 1,09,73,260 है।

देश में 16 जनवरी से कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई और अब तक कुल 2,82,18,457 लोगों को वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, भारत में शुक्रवार तक कोरोना वायरस के लिए कुल 22,58,39,273 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,40,635 सैंपल केवल कल टेस्ट किए गए।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 20,53,537 खुराक दी गई, ये एक दिन में लगाई गई वैक्सीन की सबसे अधिक संख्या है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा।

स्थानीय व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति ने कहा, यह जरूरी था क्योंकि पहले छूट थी तब लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। लोग मास्क भी नहीं लगा रहे थे न सामाजिक दूरी का पालन कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछ्ले 24 घंटों में 15,817 नए कोविड-19 मामले सामने आए और 11,344 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए वहीं 56 लोगों की मौत हो गई। यहां अब तक कुल संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 22,82,191 है और संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 21,17,744 है। वहीं अब तक यहां 52,723 संक्रमितों की मौत हो चुकी है।मिज़ोरम सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बताया, राज्य में पिछ्ले 24 घंटों में कोरोना वायरस का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। कुल

पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 4,435 है जिसमें 9 सक्रिय मामले, 4,416 डिस्चार्ज हो चुके मामले और 10 मौतें शामिल हैं।

तमिलनाडु में पिछ्ले 24 घंटों में कोविड-19 के 670 नए मामले सामने आए। 527 लोग डिस्चार्ज हुए और 6 लोगों की मौत हो गई। यहां अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,58,272 हो गया वहीं संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8,41,250 है। यहां अब तक इस संक्रमण के कारण 12,539 लोगो की मौत हो चुकी है।

कोरोना महामारी के खिलाफ साथ आए भारत-अमेरिका, 2022 तक 100 करोड़ वैक्सीन बनाने में करेगा मदद

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की चुनौती के खिलाफ क्वाड देश साथ आए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर वैक्सीन निर्माण की क्षमता बढ़ाने को लेकर भारत और अमेरिका साथ आए हैं। अमेरिका, भारत को साल 2022 के अंत तक कोरोना वायरस की 100 करोड़ वैक्सीन बनाने में मदद करेगा।अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम , भारतीय निर्माता जैविक ई लिमिटेड को 100 करोड़ वैक्सीन का निर्माण करने में सहायता करेगी। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम 2022 के अंत तक COVID-19 टीकों की कम से कम 100 करोड़ डोज का उत्पादन करने के अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए भारतीय निर्माता जैविक ई लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी।

एशिया के लिए वैक्सीन नीति

क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया की एक अहम बैठक हुई। इस अहम बैठक में कोरोना वायरस से जंग लड़ रही दुनिया को इससे निजात दिलाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें एक बड़ा फैसला ये रहा कि अमेरिकी वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन का उत्पादन भारत में किया जाएगा। इसके साथ ही एक साल के अंदर एशियाई देशों को वैक्सीन पहुंचाने का फैसला भी इस बैठक में लिया गया। क्वाड देशों की बैठक में

अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम , भारतीय निर्माता जैविक ई लिमिटेड को 100 करोड़ वैक्सीन का निर्माण करने में सहायता करेगी।

भारत की वैक्सीन कूटनीति को आगे बढ़ाने के साथ इसका समर्थन करने का भी फैसला लिया गया। देश में अमेरिका के टीके बनाने के लिए भारत अपनी विनिर्माण क्षमता का उपयोग करेगा।

'क्वाड' के डिजिटल तरीके से आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस सकारात्मक दृष्टिकोण को भारत के 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन के विस्तार के तौर पर देखता हूं, जो कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है।

कोरोना योद्धा के परिजन को सीएम ने की आर्थिक मदद, कहा- जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती

नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पूर्वी दिल्ली स्थित बाहुबली एन्क्लेव निवासी कोरोना योद्धा स्वर्गीय राकेश जैन के परिवार से मुलाकात एक करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। सीएम ने कहा कि राकेश जैन हिंदू राव अस्पताल में लैब टेक्निशियन थे। वे आखिरी दम तक लोगों की सेवा करते रहे। उन्होंने कहा कि किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं समझता हूं कि इस राशि से उनके परिवार को थोड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार उनके बेटे को नौकरी भी देगी।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सुबह पूर्वी दिल्ली स्थित बाहुबली एन्क्लेव में रह रहे कोरोना योद्धा स्वर्गीय राकेश जैन के परिवार से मुलाकात की और दिल्ली सरकार की

तरफ से उनके परिवार को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वर्गीय राकेश जैन हिंदू राव अस्पताल में लैब टेक्निशियन थे। लोगों की सेवा करते हुए उन्हें खुद भी कोरोना हो गया। उनकी तबीयत खराब होने पर मेट्रो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और वे शहीद हो गए।

स्वर्गीय राकेश जैन लैब टेक्निशियन के तौर पर आखिरी दम तक लोगों की सेवा करते रहे। ऐसे हमारे जाबांज लोग, जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा कर रहे हैं, मरणोपरांत उनके परिवार की मदद करने के लिए दिल्ली सरकार एक करोड़ रुपए की राशि देती है। आज मैं स्वर्गीय राकेश जैन के परिवार से मिल कर उन्हें एक करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। इस दौरान मैं उनकी मांता, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों से भी मिला और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन, मैं समझता हूं कि इस राशि से उनके परिवार को थोड़ी मदद मिलेगी। उनके बड़े बेटे ने ग्रैजुएशन पूरा कर ली है और नौकरी की तलाश में हैं। दिल्ली सरकार उनको नौकरी भी देगी। जब भी उनके परिवार को किसी चीज की जरूरत होगी, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने उनके परिवार को भरोसा दिया है कि उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी।

उल्लेखनीय है कि कोरोना योद्धा स्वर्गीय राकेश जैन नॉर्थ एमसीडी के हिंदू राव अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग में लैब टेक्निशियन के पद पर तैनात थे। हिंदू राव अस्पताल कोविड अस्पताल घोषित किया गया था। स्वर्गीय राकेश जैन कोरोना मरीजों की सेवा करने के दौरान खुद भी उसकी चपेट में आ गए थे और उन्हें 17 जून, 2020 को प्रीत विहार स्थित मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 18 जून 2020 को उनका निधन हो गया। स्वर्गीय राकेश जैन मूलरूप से दिल्ली के निवासी थे और 1988 में वे सेवा में आए थे। जून 2022 में वे सेवानिवृत्त होने वाले थे। इससे पहले ही वे कोविड की चपेट में आ गए। स्वर्गीय राकेश जैन अपने पीछे अपनी मां मदन श्री जैन, पत्नी संगीता जैन और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी गृहणी हैं, जबकि बड़ा बेटा ग्रैजुएशन पूरी कर सर्विस की तैयारी कर रहा है और छोटा बेटा बीए कर रहा है।

संपादकीय

होता सबका साथ तो न जाती कुरसी

त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार चार साल पूरे करने का जश्न मनाने की तैयारियां कर रही थी। राजधानी में होर्डिंग लग चुके थे। 18 तारीख को देहरादून समेत समूचे राज्य में विधानसभा क्षेत्रवार जलसे कराने का एलान किया जा चुका था। मुख्यमंत्री पूरे आत्मविश्वास से बजट सत्र के लिए शीतकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। वहां बजट भाषण के दौरान 4 मार्च को नई कमिश्नरी का एलान करके सबको चौंका दिया। भारी बहुमत वाली सरकार पर किसी तरह के संकट का आभास न था। यहां तक कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को भी इस सियासी तूफान का अंदाजा नहीं था। उत्तराखंड की विधानसभा के कुल 70 में से 57 विधायकों के भारी बहुमत वाली सरकार ने कभी सोचा तक नहीं कि हालात चार दिन में पलट जाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत को आखिरकार चार साल पूरा करने का जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिल सका और उन्हें मुख्यमंत्री पद खोना पड़ा। उत्तराखंड के लिए हालांकि, यह नया अनुभव नहीं है। 21 साल में इस राज्य ने 10 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। 11वें मुख्यमंत्री की नियुक्ति आज होने की संभावना है। भाजपा को करीब 11 साल राज्य में सरकार चलाने का मौका मिला। इस अवधि में पार्टी ने राज्य में पांच मुख्यमंत्रियों का प्रयोग कर डाला। भाजपा का एक भी मुख्यमंत्री अब तक पांच साल स्थिर सरकार नहीं दे पाया। इसके पीछे गुटीय राजनीति और असंतोष प्रमुख कारण रहे। भाजपा के मुख्यमंत्रियों में त्रिवेंद्र सिंह रावत को सबसे अधिक करीब चार साल सत्ता में रहने का मौका मिला। करीब तीन चौथाई बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को ऊपरी तौर पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जमाने की भाजपा में आम धारणा यह बनी है कि यहां मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, बदले नहीं जाते। त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी हाईकमान में अच्छी पकड़ वाला नेता भी माना जाता रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसी सुविधाजनक स्थिति में मुख्यमंत्री को कुरसी गंवानी क्यों पड़ी? दरअसल, तीन साल पूरा करते-करते कई विधायक सरकार से शिकायत करने लगे थे। सबसे पहले नौकरशाही को लेकर विधायकों की नाराजगी सामने आई। कुछ जिलाधिकारियों और सचिवालय के नौकरशाहों के रवैये पर पहले विधायकों और फिर मंत्रियों ने सवाल उठाए। कई अफसर मंत्रियों की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। खुद कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक, सतपाल महाराज, डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान, राज्य मंत्री रेखा आर्या को खुले तौर पर अफसरों को चेतावनी देनी पड़ी। कई अफसर तो मंत्रियों की बैठक में नहीं आ रहे थे। भाजपा के वरिष्ठ विधायक विशन सिंह चुफाल, पूरन फर्त्याल और राजेश शुक्ला आदि ने राज्य सरकार और पार्टी के स्तर पर ऐसे कई मामले उठाए, लेकिन इन सबको अनसुना कर दिया गया। हरिद्वार के एक विधायक ने खुलकर सरकार के खिलाफ बयान दिए। सरकार के कुछ वरिष्ठ अफसर मनमाने आदेश कर रहे थे या फिर मनमाने तरीके से उन्हें बदल रहे थे। कुछ जूनियर अफसर सीनियर अफसरों पर भारी पड़ते दिखे। आम जनता में नौकरशाही के बेलगाम हो जाने का संदेश गया। मुख्यमंत्री के हाईकमान में अच्छे संपर्कों की चर्चा अक्सर हुई, लेकिन दिल्ली में प्रदेश से जुड़े नेताओं से सामंजस्य बनाने में लापरवाही बरती गई। एक उदाहरण हाल का ही है। राज्यसभा सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पीयूष गोयल से मिलकर उत्तराखंड के लिए दो नई ट्रेनें मंजूर करवाईं। एक दिल्ली से टनकपुर और दूसरी दिल्ली से कोटद्वार। दोनों मौकों पर सरकार ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, बल्कि ट्रेन की शुरुआत के दिन कोटद्वार का नाम बदलकर कण्वनगरी कर दिया गया। इसका संदेश यह गया कि सरकार ने ट्रेन चलाने के आयोजन को काउंटर करने के लिए ऐसा किया है। माना जा रहा है कि यह मुद्दा भी पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया गया। भाजपा की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सरकार के रवैये को लेकर संतुष्ट नहीं दिख रहा था। विधायकों, मंत्रियों की नाराजगी के साथ संघ से सरकार की कथित दूरी का अर्थ है कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार 'सबका साथ' का नारा अपनी ही पार्टी में लागू नहीं कर सकी। रावत को अंदर ही अंदर चारों ओर से घेरा जा रहा था और उन्हें भनक तक नहीं लगी। त्रिवेंद्र सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपने काम दिखा नहीं पाई। इस सरकार ने 2018 में धर्मांतरण करके बिना बताए शादी करने पर रोक का कानून बना दिया था। पर उसके करीब दो साल बाद लव जेहाद के खिलाफ ऐसा ही कानून बनाकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देश भर में खूब प्रचार पा लिया, पर त्रिवेंद्र सरकार का राज्य से बाहर जिक्र तक नहीं हुआ। मीडिया के एक हिस्से में उत्तर प्रदेश को ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला प्रदेश बताया जा रहा था, जबकि हिमाचल प्रदेश ऐसा कानून 2006 से पहले ही बना चुका है। उत्तराखंड के हर आदमी को पांच लाख का मुफ्त इलाज देने से लेकर किसानों-बागवानों के लिए नई योजनाएं बनीं। लेकिन लचर प्रचार तंत्र के कारण लोगों तक ये बातें ठीक से नहीं पहुंचीं। शीतकालीन राजधानी बनाने, बोर्डों, निगमों में अध्यक्ष, उपाध्यक्षों की नियुक्ति और गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने जैसे बड़े फैसले करते वक्त रावत ने विधायकों और पार्टी संगठन के बड़े नेताओं को विश्वास में नहीं लिया। इसका असर यह हुआ कि नई कमिश्नरी में अल्मोड़ा को शामिल करने केविरोध केकेंद्र में मुख्यमंत्री खुद आ गए। नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है। अगले सीएम के पास काम करने के लिए दिसंबर तक का समय होगा। दिसंबर में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। सबसे अहम सवाल है कि जो चार साल में नहीं हो पाया, क्या नए मुख्यमंत्री नौ माह में उसे कर पाएंगे? असंतुष्ट विधायकों को मनाकर उनका सहयोग लेना, अफसरशाही को नियंत्रित करके उससे तेजी से काम लेना टेढ़ी खीर है। नए मुख्यमंत्री तेजी से कामकाज कर संदेश नहीं दे पाए, तो आम जनता के बीच धारणा बनाना कठिन हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि नए मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के बीच शुरुआती एक माह में ही उत्साहजनक प्रदर्शन करना होगा। अगर वह विधायक दल, पार्टी और मतदाताओं के बीच 'सबका साथ' के नारे का संदेश देने में सफल हो गए, तो भाजपा में नए नायक बन जाएंगे।

प्रवीण कुमार सिंह

तथ्यों को जाने बिना डिजिटल मीडिया के नए नियमों के बारे में फैला रहे अनावश्यक भ्रांतियां

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के खंड तीन को लागू करने का अधिकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की जगह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का संदर्भ दिया गया है और इस सिलसिले में कोई भी नया प्रविधान नहीं किया गया है। यह प्रविधान आपातस्थिति के लिए किया गया है और 48 घंटे के भीतर इसकी पुष्टि भी करानी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया तो क्या हमें शिकायत दायर किए जाने का इंतजार करना चाहिए या इसे हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए? एक दूसरा उदाहरण कुछ दिनों पहले एक राज्य से आया, जहां जिला मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक न्यूज पोर्टल को नोटिस भेज दिया।

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 'सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021' की घोषणा की। ये नियम समान अवसर प्रदान करने के साथ एक प्रगतिशील संस्थागत तंत्र स्थापित करते हैं, जिसकी आचार संहिता और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का पालन डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी सामग्री के प्रकाशकों को करना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पांच आयु आधारित श्रेणियों में सामग्री को स्व-वर्गीकृत करेगा। डिजिटल मीडिया पर खबरों के प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद की पत्रकारिता नियमावली और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियामकीय अधिनियम की कार्यक्रम संहिता का पालन करना होगा, जिससे ऑफलाइन (प्रिंट, टीवी) और डिजिटल मीडिया के बीच समान अवसर उपलब्ध हों। दुख की बात है कि कुछ संशयवादियों ने इन नियमों को सेंसरशिप लागू करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और यहां तक कि उन्हें तानाशाही तक करार दिया है।

पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री के मुद्दे को लेते हैं। वास्तव में स्वतंत्र भारत में पहली बार पांच अलग-अलग आयु समूहों में स्व-वर्गीकरण की अधिक पारदर्शी प्रणाली के लिए पूर्व-प्रमाणीकरण या सेंसरशिप से अलग एक नीति की बात की गई है। अगर हम विभिन्न देशों में ओटीटी वर्गीकरण पर विचार करते हैं तो सिंगापुर में इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ब्रॉडकास्टिंग एक्ट, 1994 के तहत स्थापित है, जहां विभिन्न मीडिया के लिए सामान्य मीडिया नियामक निकाय हैं। ओटीटी, वीडियो-ऑन-डिमांड और विशिष्ट सेवाओं के लिए वहां एक मार्च, 2018 से कंटेंट कोड प्रभाव में आया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन मीडिया को ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज एक्ट, 1992 के माध्यम से

विनियमित किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम, 2015 को और जोड़ा गया है। ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए ई-सेफ्टी कमिश्नर का कार्यालय नियामक प्राधिकरण होता है।

इस प्रकार ओटीटी सामग्री का स्व-वर्गीकरण कई देशों में एक स्वीकृत मानदंड है, किंतु ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगाए जाने का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि यह कदम रचनात्मक लोगों को सामग्री के स्व-वर्गीकरण की सुविधा देता है। कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा एक और मुद्दा उठाया जा रहा है कि शिकायत निवारण तंत्र में उनकी बहुत कम भूमिका है। एक वेबसाइट ने तो फेक न्यूज भी चला दी कि शिकायत निवारण तंत्र के जजों की नियुक्ति केंद्र सरकार के पैनल से की जाएगी। यह पूर्णतया असत्य है। नए नियम की धारा-12(2) के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्व-नियामक निकाय की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव अधिकार और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों से एक स्वतंत्र एवं विख्यात व्यक्ति करेंगे। अन्य सदस्य, जिनकी कुल संख्या छह से अधिक न हो, मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानव अधिकार और ऐसे ही अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। स्पष्ट है स्व-विनियमन तंत्र के टियर-1 या टियर-2 में किसी भी सरकारी हस्तक्षेप की बात नहीं। स्व-नियामक निकाय के टियर-2 का गठन खुद ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा ही किया जाना है।

ओटीटी प्लेटफॉर्मों द्वारा उल्लिखित तीसरा मुद्दा उनके साथ परामर्श की कमी से संबंधित है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने स्वयं दो मार्च, 2020 को दिल्ली में ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इससे पहले मंत्रालय ने 10 नवंबर, 2019 को मुंबई में और 11 नवंबर, 2019 को चेन्नई में ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म लंबे समय से मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि परामर्श की भी समय सीमा होती है।

डिजिटल समाचार पोर्टलों के लिए भी पत्रकारिता संहिता का पालन करना जरूरी होगा, जो भारतीय प्रेस परिषद के समान है। उन्हें प्रेस काउंसिल एक्ट, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स, 1994 के जर्नलिस्टिक कोड के मानदंडों का पालन करना होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंधित सामग्री प्रसारित नहीं होनी चाहिए। यह समझना मुश्किल है कि यह आचार संहिता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कैसे अंकुश लगा सकती है? सरकार से सवाल करने के बजाय सभी डिजिटल न्यूज पोर्टल को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उन्होंने इतने लंबे समय तक अपना कोड विकसित करने में कोई पहल क्यों नहीं की? डिजिटल न्यूज पोर्टल का एक और दायित्व अपने बारे में जानकारी और शिकायत निवारण तंत्र प्रस्तुत करने से संबंधित है। आश्चर्य है कि कई समाचार पोर्टल आम नागरिकों को अगर कोई शिकायत है तो उन्हें ईमेल करने का भी कोई अवसर नहीं देते।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के खंड तीन को लागू करने का अधिकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की जगह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का संदर्भ दिया गया है और इस सिलसिले में कोई भी नया प्रविधान नहीं किया गया है। यह प्रविधान आपातस्थिति के लिए किया गया है और 48 घंटे के भीतर इसकी पुष्टि भी करानी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया तो क्या हमें शिकायत दायर किए जाने का इंतजार करना चाहिए या इसे हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए? एक दूसरा उदाहरण कुछ दिनों पहले एक राज्य से आया, जहां जिला मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक न्यूज पोर्टल को नोटिस भेज दिया। वहां भी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रकाशक/संपादक की शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना ही तुरंत राज्य सरकार को सूचित किया कि जिला मजिस्ट्रेट को ये शक्तियां नहीं दी गई हैं और कुछ ही घंटों में जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिस वापस ले लिया।

जो लोग डिजिटल मीडिया के संबंध में लाए गए नए नियमों के खिलाफ अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि पहले तथ्यों को जान लें। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। अपने मन के दरवाजे खोल कर उसमें कुछ प्रकाश आने दें। सही चीजें अपने आप दिखने लगेंगी।

देश के अधिकांश हिस्सों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रमुख दायित्व

अत्यधिक दोहन के कारण भूजल का स्तर देश में नीचे जा रहा है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत भाग निवास करता है, जबकि पीने योग्य पानी चार प्रतिशत ही उपलब्ध है। निरंतर कम हो रही वर्षा, भूजल का गिरता स्तर तथा जल स्नोतों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैसे कारणों से निरंतर जल की उपलब्धता कम होती जा रही है। इससे दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी आबादी को भी पानी उपलब्ध करा पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसे दृष्टि में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा कर 2024 तक देश के हर घर में जल पहुंचाने की जल जीवन मिशन की घोषणा की थी और जल मंत्रलय को जल शक्ति मंत्रलय के रूप में स्थापित करते हुए समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त बजट की व्यवस्था की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के तहत 50,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जिसके अंतर्गत 2.86 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से अर्बन जल जीवन की शुरूआत की जाएगी। अर्बन जल जीवन मिशन का लक्ष्य सभी शहरी स्थानीय निकायों में हर घर नल से जल पहुंचाना सुनिश्चित करना है। ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने की योजना में बिहार सबसे आगे है। इसके बाद मिजोरम और हरियाणा का स्थान है। देश में इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण घरों को नल से जोड़ने का कार्य समस्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बंगाल में सबसे कम मात्र 1.44 प्रतिशत ही अब तक किया जा सका है।

आज देश के बड़े भूभाग में निरंतर जल संकट उत्पन्न होने, भूगर्भ जलस्तर के नीचे जाने तथा जल स्नोतों के निरंतर नष्ट होते जाने के कारण जल की उपलब्धता को बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है। इजराइल से प्राप्त सूचना एवं तकनीकी का प्रयोग कर उपलब्ध जल को पाइपलाइन के माध्यम से घर घर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज भारत में भूजल का चार प्रतिशत पेयजल के रूप में तथा 80 प्रतिशत से अधिक खेती की सिंचाई में इस्तेमाल हो रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनसंख्या में से लगभग 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। स्वच्छ पेयजल नहीं मिलने से देश में हर साल लगभग दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। आज देश में लगभग 4,500 छोटी छोटी नदियां और लगभग 20 हजार तालाबों ने अपना अस्तित्व खो दिया और उससे भी अधिक निकट भविष्य में अपना अस्तित्व खोने के कगार पर हैं। जल स्नोतों की निरंतर हो रही कमी के कारण भूजल समाप्त हो रहा है और हमारे अधिकांश शहर भूजल समाप्त हो जाने के कारण जल संकट की गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। देश के महानगरों समेत अधिकांश प्रमुख शहरों में जल संकट की स्थिति गंभीर हो चुकी है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के अनुसार देश में औसतन 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक है, किंतु जल की उपलब्धता की यह मात्र औसत 69 लीटर पर आकर रुक जाती है। भारत के करीब 54 प्रतिशत भूभाग पर भूजल तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। संभावित जल संकट को देखते हुए वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत लोगों को ही पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। वर्ष 2050 तक यही स्थिति बनी रही तो जीडीपी का छह प्रतिशत पानी पर ही खर्च होगा। उपलब्ध जल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हर घर तक नल के माध्यम से 2024 तक जल पहुंचाने की योजना असंभव तो नहीं, किंतु कष्ट साध्य एवं श्रम साध्य अवश्य प्रतीत हो रही है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के कार्य में सफलता के लिए आवश्यक है प्रचुर मात्र में जल का उपलब्ध होना। यद्यपि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलों के माध्यम से घर घर जल पहुंचाने की योजना बनाते हुए तरल अपशिष्ट पदार्थो के प्रबंधन के साथ-साथ भूगर्भ जलस्तर संवर्धन एवं जल संवर्धन तथा संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है, किंतु योजना की सफलता तभी संभव है, जब आवश्यकतानुसार प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। जल जीवन मिशन योजना को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारें अपने दायित्व को भली-भांति समझें तथा उसका निर्वहन करें और भूजल के व्यापक दोहन पर प्रतिबंध लगाएं। बिना अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार की ट्यूबवेल लगाए जाने पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। भले ही वह सिंचाई के लिए हो या पीने के पानी के लिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां नल से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, वहां पर भूजल के दोहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, तभी भूजल संरक्षण एवं संवर्धन को गति मिलेगी तथा जल जीवन मिशन के साथ-साथ अर्बन जल मिशन के अंतर्गत घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना सफल होगी।

चुनाव में चोटिल होना

बुधवार को नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के बाद जिस तरह के घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हुईं और फिर जिस तरह का माहौल बना, वह पूरा प्रकरण चिंताजनक है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक उनके पांव, कंधे और गर्दन में चोटें आई हैं। अगले दिन हॉस्पिटल बेड पर उनकी तस्वीरें भी आईं जिनमें उनके बाएं पैर में प्लास्टर दिख रहा है। इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि क्या हुआ और कैसे हुआ। इसके साथ ही ममता बनर्जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना प. बंगाल के चुनाव से किसी भी रूप में जुड़े हर राजनेता को बिना किसी हीलाहवाली के करनी चाहिए। जो बात इस प्रकरण में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, वह यह कि चुनावी लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ने के आदी होते जा रहे हमारे राजनीतिक दलों में पारस्परिक शिष्टाचार के न्यूनतम विवेक की भी किल्लत होती जा रही है।

ममता के घायल होने की खबर आते ही उनकी हालत को लेकर जानकारी हासिल करने और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताने के बजाय चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा आक्रामक होकर चुनौती दे रही पार्टी के छोटे-बड़े तमाम नेताओं ने यह संदेह जताना शुरू कर दिया कि ममता ने हमले की फर्जी कहानी रची है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बात ही छोड़िए, केंद्रीय मंत्रियों में से भी किसी ने घटना की निंदा करते हुए या ममता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कोई ट्वीट नहीं किया।

झकांग्रेस के असंतुष्ट खेमे के एक नेता आनंद शर्मा ने जरूर यह औपचारिकता निभाई, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनावों में पार्टी की अगुआई कर रहे अधीर रंजन चौधरी ने साफ-साफ कहा कि ममता ने लोगों की सहानुभूति पाने के लिए यह पाखंड रचा है। दिलचस्प बात यह कि खुद ममता बनर्जी का व्यवहार भी इस मामले में कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के ही दक्षिण 24 परगना जिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव की खबर आई थी तो ममता बनर्जी ने उसकी सत्यता पर इसी तरह सवाल उठाते हुए संदेह जताया था कि हमले की फर्जी शिकायत की जा रही है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह सर्वथा नई परिस्थिति है। चुनावी लड़ाइयां तो हमेशा से होती रही हैं। इन लड़ाइयों में दांव पर सत्ता भी हमेशा लगी होती है।

बावजूद इसके, अगर पिछले सात दशकों में विचारों, नीतियों और मुद्दों को नेताओं की निजी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से अलग रखना संभव बना रहा तो कोई कारण नहीं कि अब ऐसा न हो सके। अगर आज ऐसा होता नहीं दिख रहा तो इसके कारण निश्चित रूप से आज की हमारी राजनीतिक संकीर्णता, ओछेपन और हद दर्जे की स्वार्थप्रियता में ही निहित होंगे। लेकिन कारण ढूंढ लेना समस्या के समाधान के लिए कभी काफी नहीं होता। समझना जरूरी है कि चुनावी हार-जीत को आत्मिक मूल्यों से ऊपर रखने की इस प्रवृत्ति पर अगर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो आम लोगों में दलीय तनाव बहुत बढ़ जाएगा और देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में पड़ जाएंगी।

इन्हें वोट देने का तो अधिकार है, किंतु नागरिकता उनके लिए भावनात्मक मुद्दा है

मतुआ धर्म महासभा शरणार्थियों के सवाल पर लगातार मुखर रहा। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों में सर्वाधिक संख्या दलितों की है। आश्चर्य है कि जो दल दलितों के हितैषी होने का दावा करते हैं, उन्होंने मतुआ समुदाय के लोगों की नागरिकता का सवाल कभी नहीं उठाया। मतुआ समाज का दशकों से नागरिकता के लिए प्रतीक्षारत रहना यही बताता है कि कैसे देश ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से जान बचाकर आए कुछ पीड़ित-प्रताड़ित लोगों को भुला दिया? मतुआ धर्म महासंघ समाज के दबे-कुचले तबके के उत्थान के लिए काम करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल आबादी के 23.5 प्रतिशत दलित और 5.8 प्रतिशत आदिवासी हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ मतुआ समुदाय एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस चर्चा ने तबसे और जोर पकड़ा है, जबसे यह सूचना आई है कि प्रधानमंत्री अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान मतुआ समुदाय के गुरु हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली जा सकते हैं। उन्होंने ही मतुआ धर्म महासंघ की स्थापना की थी। यह महासंघ बंगाल में दलितों का सबसे बड़ा आंदोलन है। बंगाल में इस संघ के सदस्यों की संख्या करीब पौने दो करोड़ है और उनका 70 से अधिक विधानसभाओं में असर है। बंगाल के बाहर भारत के विभिन्न राज्यों में फैले बांग्लादेशी शरणार्थी भी इस संघ के समर्थक हैं। मतुआ आंदोलन पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) से पश्चिम बंगाल आया। हरिचंद ठाकुर ने उन्नीसवीं शती के मध्य में पूर्वी बंगाल के गोपालगंज में मतुआ धर्म महासंघ की स्थापना की थी।

पूर्व और पश्चिम बंगाल में दलितों को धर्म का अधिकार सबसे पहले हरिचंद ठाकुर के मतुआ संघ ने ही दिया। मतुआ यानी जो मतवाले हैं। जो जाति, धर्म, वर्ण से ऊपर उठे हुए हैं। हरिचंद ठाकुर ने मुख में नाम, हाथ में काम और सबको शिक्षा के अधिकार का नारा दिया और दलितों के लिए अनेक स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने जीव मात्र से दया करने की शिक्षा दी थी। हरिचंद ने अपने महासंघ के लोगों को दूसरों से स्नेह, दूसरे के प्रति सहनशीलता, स्त्री-पुरुष में समानता, जाति आधारित भेदभाव को नहीं मानने के साथ लालची नहीं होने की शिक्षा दी थी। धीरे-धीरे उनके संदेशों का असर होने लगा। झुंड के झुंड लोग उनके अनुयायी बनने लगे और मतुआ धर्म महासंघ आकार लेने लगा। हरिचंद ठाकुर के निधन के बाद मतुआ महासंघ को उनके पुत्र गुरुचंद ठाकुर ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा था, 'जार दल नेई, तार बल नेई।' यानी जिनका दल नहीं, उनका बल नहीं। परवर्ती काल में मतुआ आंदोलन को बढ़ाने का काम गुरुचंद के पौत्र प्रमथ रंजन विश्वास, रसीकलाल विश्वास, मुकुंद बिहारी मल्लिक, विराटचंद मंडल और विश्वदेव दास ने किया।

देश विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ने लगा तो मतुआ धर्ममहासंघ के अनुयायी बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल समेत भारत के विभिन्न राज्यों में आने लगे। स्वयं गुरुचंद के पौत्र प्रमथ रंजन विश्वास भी 13 मार्च, 1948 को पश्चिम बंगाल के बनगांव आ गए और एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। मतुआ धर्म की तरह जोगेंद्रनाथ मंडल भी बांग्लाभाषी समाज में दलितों के जागरण के लिए समर्पित होकर काम करते रहे थे। देश विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल को जब पाकिस्तान में मिलाने की बात आई तो प्रारंभ में उसका मंडल ने विरोध किया, लेकिन अंततः देश विभाजन होने पर वे पूर्वी बंगाल में ही रह गए और जिन्ना के विश्वासपात्र बन गए। पूर्वी बंगाल यानी तत्कालीन पाकिस्तान में दलितों की स्थिति में सुधार लाने का सपना लेकर जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान की पहली कैबिनेट में कानून और श्रम मंत्री बने, लेकिन लाख कोशिश कर भी वह अपने सपने को पूरा नहीं कर सके। पाकिस्तान सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मंडल पश्चिम बंगाल आए और डॉ. आंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम करते रहे।। मंडल स्वयं नम शूद्र समुदाय से थे। उस समुदाय के हितों की रक्षा के लिए वे निरंतर आंदोलनरत रहे। इससे उनकी जनप्रियता इतनी बढ़ी कि उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को बंगाल से लड़ाया और जिताया भी। 1968 में बनगांव में पार्टी के लिए प्रचार करते हुए उनकी तबियत खराब हुई और वे चल बसे।

जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे नेताओं और मतुआ धर्म महासंघ के प्रयासों से बंगाल में दलित आंदोलन का विस्तार सुदूर जिलों तक में हो गया। गुरुचंद के पौत्र प्रमथ रंजन विश्वास ने 1948 के बाद बंगाल में मतुआ धर्म महासंघ को संगठित करने का निरंतर यत्न किया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी वीणापाणि देवी (बड़ो मां) मतुआ धर्म की सबसे बड़ी नेता बनीं। वीणापाणि देवी वह पहली शख्स थीं, जिन्होंने बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने की मांग की थी। यह मांग आज भी अधूरी है। भाजपा ने इसे नागरिकता संशोधन कानून के तहत पूरा करने का आश्वासन दिया है। हालांकि मतुआ समुदाय को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन नागरिकता उनके लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। मतुआ धर्म महासभा शरणार्थियों के सवाल पर लगातार मुखर रहा। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों में सर्वाधिक संख्या दलितों की है। आश्चर्य है कि जो दल दलितों के हितैषी होने का दावा करते हैं, उन्होंने मतुआ समुदाय के लोगों की नागरिकता का सवाल कभी नहीं उठाया। मतुआ समाज का दशकों से नागरिकता के लिए प्रतीक्षारत रहना यही बताता है कि कैसे देश ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से जान बचाकर आए कुछ पीड़ित-प्रताड़ित लोगों को भुला दिया? मतुआ धर्म महासंघ समाज के दबे-कुचले तबके के उत्थान के लिए काम करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल आबादी के 23.5 प्रतिशत दलित और 5.8 प्रतिशत आदिवासी हैं। बंगाल के दलित एवं आदिवासी मतुआ धर्म महासंघ के स्वाभाविक समर्थक माने जाते हैं। उत्तर 24 परगना जिले में बनगांव स्थित मतुआ धर्म महासंघ के मुख्यालय में मतुआ माता वीणापाणि देवी के साथ गत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी। वीणापाणि देवी के दबाव में ही ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली पश्चिम बंगाल सरकार को मतुआ कल्याण परिषद का गठन करना पड़ा। वीणापाणि देवी का गत वर्ष निधन हो गया। अब उनके पुत्र और पौत्र मतुआ आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में उनका मत निर्णायक साबित होगा।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव पटना में अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ।

यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस देख शुरू होगी फोकस टेस्टिंग, प्रदेश भर में चलेगा अभियान

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में दोबारा कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार से फिर पूरे राज्य में फोकस टेस्टिंग शुरू की जाएगी। कोरोना जांच के लिए बाजारों में दुकानों में काम कर रहे कर्मियों, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों, जेलों व वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों तक चलने वाले फोकस टेस्टिंग अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। बीते महीने फरवरी में भी फोकस टेस्टिंग अभियान चलाया गया था।

उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार को देखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए शनिवार से फोकस टेस्टिंग की जाएगी। यह विशेष अभियान 27 मार्च तक चलाया जाएगा। समुदाय स्तर पर संक्रमण का पता लगाने के लिए फोकस टेस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान दुकानों और शॉपिंग मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों, खरीददारी करने वाले लोगों, पटरी दुकानदारों के नमूने लिए जाएंगे। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाकर उनको क्वारंटीन किया जाएगा। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों की जांच होगी।

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के साथ-साथ कांटैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया जाएगा। लोगों के घर-घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के बारे में सर्तक करेंगे और लक्षण वाले रोगियों की जांच कराएंगे। उधर, मार्च में प्रतिदिन किए जा रहे टेस्ट की रफ्तार धीमी है। फरवरी में प्रत्येक दिन कभी भी एक लाख से कम टेस्ट नहीं हुए और अधिकतम 1.40 लाख तक लोगों की जांच हुई। वहीं मार्च में एक दिन में अधिकतम 1.18 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। शुक्रवार को 90 हजार और आठ मार्च को जांच के लिए 83 हजार सैंपल ही लिए गए थे। फिलहाल अब फोकस टेस्टिंग के साथ-साथ प्रतिदिन होने वाली जांच को भी बढ़ाया जाएगा।

केस बढ़ने से अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग : यूपी में कोरोना संक्रमण के रोगी दोबारा बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को एक महीने बाद सर्वाधिक 167 नए रोगी मिले। इससे पहले तीन फरवरी को 197 संक्रमित मरीज मिले थे। देश में महाराष्ट्र व केरल सहित पांच राज्यों में संक्रमण में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बाद अब यूपी में हर दिन ज्यादा मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 90 हजार लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। नए मिल रहे मरीजों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या भी कम है।

अब तक 8,743 लोगों की हो चुकी है मौत : उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में नए मिले मरीजों के मुकाबले 88 रोगी ही ठीक हुए हैं। बीते चार दिनों से लगातार नए मरीजों के मुकाबले कम रोगी स्वस्थ हो रहे हैं। अभी तक कुल 6.04 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 5.94 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को दो और मरीजों की मौत होने के बाद अभी तक 8,743 लोगों की जान यह वायरस ले चुका है।

संक्षिप्त खबर

बरेली में तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला ने मांगी माफी, वायरल पत्र में कही यह बात...

बरेली । तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाकर चर्चा में आई महिला के नाम से एक तौबानामा (माफीनामा) शुक्रवार रात को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। पत्र में लिखा है कि वह तीन तलाक से जुड़े हर नियम को शरीयत के अनुसार मानती हैं। दरगाह आला हजरत से जुड़े लोगों ने इस तौबानामा की तस्दीक की है, लेकिन यह किसका है, यह स्पष्ट नहीं।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक परिवार की एक बहू का मामला कुछ साल पहले सामने आया था, जिसमें महिला ने शौहर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला ने कहा था कि निकाह के कुछ समय बाद ही तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने शौहर सहित अन्य ससुरालियों पर कानूनी कार्रवाई की थी। मामला अदालत में गया, जिसके बाद उनके खिलाफ फतवे जारी हुए थे। इस्लाम से खारिज करने की बात भी कही गई थी। यह मामला लंबे समय सुर्खियों में बना रहा था। शुक्रवार को एक बार फिर यह मामला गर्मा गया। उसी महिला के नाम से लिखा गया तौबानामा इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़िता ने तौबानामा पत्र पर अंग्रेजी में साइन किए हैं। इसमें पांच गवाहों को लिया गया है, जिसमें तीन महिला और दो पुरुष के हस्ताक्षर हैं। दरगाह से जुड़े लोगों ने तौबानामा की तस्दीक भी की है। दरगाह सूत्रों के अनुसार, महिला के एक रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था। मुहल्ला सुर्खा में महिला ने तौबानामा लिखकर दिया। तौबानामा में यह लिखा : महिला ने तौबानामा में लिखा है कि मैं आला हजरत की जुमला तालिमात और उसके हर फतवे को जानती व मानती हूं। आला हजरत के फतवा बिल खुसूस निकाह, तलाक व हलाला के मसाइल में जो भी हुक्मे शरई है, मैं उसे सही मानती हूं। खिलाफत में मैंने जाने-अनजाने जो भी बात कही या लिखी या उस पर राजी हुई, मैं गवाहों के बीच तौबा व रुजू (वापस) करती हूं। दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता नासिर कुरैशी ने बताया कि महिला का तौबानामा इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने की जानकारी हुई है। तौबा पत्र में शामिल एक गवाह ने इसकी पुष्टि भी की है। निदा के नाम से जारी हुआ तौबानामा : कहा जा रहा है कि जो तौबानामा (माफीनामा) जारी हुआ है, वह किसी निदा खान का है। इस मामले की पुष्टि करने के लिए तीन तलाक पीड़िताओं की लड़ाई लड़ने वाली निदा खान से फोन पर बात करने की कोशिश की, मगर रिसीव नहीं हुआ। मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। यह पुष्ट नहीं हुआ है कि तौबानामा लिखने वाली निदा खान कौन सी हैं।

उत्पाद विभाग की टीम को सड़क पर देख शराब लदी ट्रक किनारे लगा फरार हो गया चालक

औरंगाबाद । उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार सुबह में नगर थाना क्षेत्र के रामाबांध बस स्टैंड के पास से ट्रक पर लदा बड़ी मात्रा में शराब को जब्त किया है। ट्रक से 400 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक सीमा चौरसिया ने बताया कि शराब के खिलाफ चलाई जा रही वाहन जांच अभियान के दौरान झारखंड के हरिहरगंज की तरफ से शराब लदी ट्रक आ रही थी। छापामारी टीम को देखकर चालक ने ट्रक को कुछ दूर खड़ा कर फरार हो गया। ट्रक को रुकने के बाद छापामारी टीम पहुंची तो उसे जांच की। जांच के दौरान ट्रक पर लदे शराब की पेटी को देखा गया। मौके पर ही शराब लदी ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक चालक, सहचालक भागने में सफल रहे। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि छापामारी टीम में उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, कुमकुम कुमारी, एसआइ कमलेश कुमार सिन्हा एवं निधि कुमारी के साथ पुलिसबल शामिल रहे। बताया कि जब्त शराब लदी ट्रक का निबंधन संख्या बंगाल की है। ट्रक का मालिक कौन है इसकी तहकीकात परिवहन विभाग कार्यालय से की जा रही है।

उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जब्त शराब होली पर्व को लेकर स्टॉक करने के लिए ले जाया जा रहा था। शराब कहां खपाना था इसकी जांच की जा रही है। मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत ट्रक मालिक एवं चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि होली पर्व को लेकर झारखंड से प्रतिदिन शराब की खेप आ रही है। अगर पुलिस से बच जा रही है तो धंधेबाज अपनी धंधे में सफल हो जा रहे हैं। उधर शराब के खिलाफ जिला पुलिस से लेकर उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा प्रतिदिन छापामारी अभियान एवं वाहनों की जांच अभियान चलाया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में अपराध नियंत्रण का यह हाल, दारोगा की ही बाइक उड़ा ले गए चोर

मुजफ्फरपुर । शातिर चोरों पर नकेल नहीं कसने का नतीजा है कि अब वे पुलिसकर्मी की बाइक को भी निशाना बना ले रहे हैं। गुरुवार की रात मझौलिया रसुलपुर जिलानी इलाके से एएसआइ कृष्ण कुमार सिंह के घर से उनकी बाइक की चोरी कर ली गई। मामले में उन्होंने काजीमोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वे इसी थाने में तैनात भी है। चोरों का पता लगाने के लिए आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। मगर कोई सुराग नहीं मिल पाया। बता दें कि शहरी क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही है। बावजूद पुलिस की तरफ से शातिर चोरों की गिरफ्तारी को लेकर रुचि नहीं लिया जा रहा है। वहीं चोरी का मोबाइल खरीदना दरभंगा के एक किशोर को महंगा पड़ गया। गोंडा जीआरपी पुलिस ने जाले थानाक्षेत्र के जाले हीरानगर गांव में छापेमारी कर किशोर को मोबाइल के साथ दबोच लिया। पूछताछ में किशोर ने जो जानकारी दी वह सुन पुलिस पदाधिकारी अवाक रह गए। किशोर को लेकर पुलिस मुजफ्फरपुर गई। जहां सीसी कैमरा के फुटेज से उसका मिलान कराया गया। लेकिन, फुटेज में उसकी तस्वीर नहीं पाई गई। इसके बाद पुलिस ने बाउंड बनाकर तत्काल किशोर को छोड़ दिया। दरोगा विजय यादब ने बताया कि सप्तक्रांति ट्रेन से सैनिक राहुल प्रताप सीतामढ़ी एसएसबी कैंप जा रहे थे। इस दौरान उनका मोबाइल सहित बैग चोरी हो गया। इस मामले को लेकर पीड़ित सैनिक ने गोंडा जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच दौरान मोबाइल को जब ट्रैक किया गया तो वह जाले थानाक्षेत्र में पाया गया। इसके तहत वहां की पुलिस स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। इधर, किशोर ने बताया कि वह दिल्ली से आ रहा था। इस दौरान उसका बड़ा भाई पांच हजार रुपया दिया था।

सीएम योगी ने नव नियुक्त बीईओ को दिए नियुक्ति पत्र, बोले- चार साल में दीं चार लाख सरकारी नौकरियां

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेरोजगारों के लिए राज्य में मिशन रोजगार चला रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद के नव नियुक्त 271 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चार वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान प्रदेश में चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल हुए हैं। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति पत्र देकर उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए ले पाने में सफल हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शिता के साथ चयन की बात करते हुए बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले जाति और क्षेत्र के आधार पर नियुक्ति होती थी। एक खानदान के लोगों में भर्तियां बंट जाती थीं कि ये चाचा देखेंगे, ये मामा और ये भैया। जैसे महाभारत में एक परिवार था। योगी ने तंज कसा कि यह महाभारत के ही पात्र हैं, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है।

चार वर्ष में सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में एक लाख बीस हजार भर्तियों का दावा करते हुए सीएम आदित्यनाथ सरकार ने खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा कि प्रतियोगी छात्र के रूप में आपको जो अपेक्षा शासन से रही होगी, वही अपेक्षा आज शासन को आपसे है। बच्चों की नींव मजबूत करने का दायित्व आप पर है। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग नौकरी शुरू करते ही भ्रष्टाचार से घिर जाते हैं। उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं। फिर उन्हें बर्खास्त करना पड़ता है। ध्यान रखें कि कोई बीमार है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर छुट्टी दें, पैसा लेकर नहीं। कार्यक्रम को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चंद्र द्विवेदी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा संजीव मित्तल ने भी संबोधित किया।

जाति और मजहब देखकर दी जाती थी नियुक्तियां : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से चार वर्ष पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की गरिमा दांव पर लगी थी। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब देखकर नियुक्तियां दी जाती थी। धनबल और बाहुबल का का भरपूर दुरुपयोग होता था। उन स्थियों में पारदर्शिता और

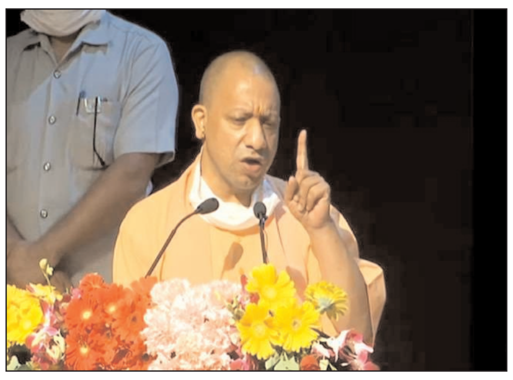

सुचिता कपोल कल्पना मात्र थी। लेकिन, आज सभी चयन आयोगों से पारदर्शी तरीके से अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। सरकार ने आयोगों और बोर्डों को पहले ही कह दिया था कि कहीं भी पक्षपात या भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। इसकी का परिणाम है कि आज कोई भी युवा भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करता है।

डेढ़ लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश में हर दूसरे-तीसरे दिन बड़ा दंगा होता था, जिसमें काफी संपत्ति की हानि होती थी। इन दंगों के कारण प्रदेश की छवि प्रभावित होती थी। आम आदमी परेशान होते थे। इस दौरान नियंत्रण के लिए पुलिस बल की आवश्यकता थी, लेकिन पुलिस कर्मियों की संख्या कम थी। तीन लाख की बजाए सवा लाख बल ही मौजूद था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उसकी 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। तब प्रदेश सरकार ने कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया होनी है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। इसी का परिणाम है कि चार वर्षों के दौरान डेढ़ लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई।

भर्तियों के बहाने पूर्व सरकार पर किया कटाक्ष : कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने नव नियुक्त अभ्यर्थियों से पूछा कि भर्ती के दौरान किसी को सिफारिश की आवश्यकता पड़ी? जवाब नहीं में आया तो सीएम योगी ने फिर पूछा कि किसी अधिकारी नेता, मंत्री या उनके घर के लोग आपसे पैसे वसूलने के लिए आए हों? इसका भी जवाब नहीं में आया तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले ऐसा होता था। कोई खानदान था जिनमें अलग-अलग भर्ती आवंटित हो जाती थी कि ये भर्ती चाचा देखेंगे, ये भर्ती भाई देखेंगे या भतीजा देखेगा। ये चाचा, काका, मामा ये महाभारत काल में सुने होंगे या फिर वर्ष 2012 से 2017 के बीच में सुने होंगे। ये महाभारत के वही पत्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। वे लोग जैसे महाभारत करते भारत की प्रगति को बाधित किए थे वैसे ही इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया।

309 पदों पर निकली गई थी भर्ती : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए 309 पदों पर विज्ञापन निकाला था, जिसमें से 271 सफल घोषित हुए। प्रदेश में 12 साल बाद खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की मुख्य परीक्षा में 271 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की मुख्य परीक्षा 6 दिसंबर, 2020 को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में कुल 4182 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

बिहारः सुपौल ने दिलाई बुराड़ी कांड की याद, इसबार नए कपड़े पहन फांसी पर झूला पूरा परिवार

पटना । दिल्ली का बुराड़ी कांड किसे नहीं याद होगा। आज भी एक साथ परिवार के 11 लोगों की आत्महत्या की याद रोंगटे खड़े कर देती है। बुराड़ी इलाके के संत नगर में एक जुलाई 2018 को भाटिया परिवार में हुई घटना की यादें बिहार के सुपौल ने एकबार फिर ताजा कर दी हैं। शनिवार की सुबह सुपौल में मिश्रीलाल साह सहित उनके परिवार के पांच सदस्य फांसी के फंदे से झूलते मिले। बड़ी बात ये रही कि मौत को गले लगाने से पहले परिवार के सभी सदस्यों ने अच्छा खाना खाया था और नए कपड़े पहने थे।

एक ही कमरे में पांच थे लटके- सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी गांव के वार्ड चार में एक घर के अंदर से एक ही परिवार के पांच सदस?यों के शव मिले। सभी शव घर के अंदर एक ही कमरे में फंदे से लटके मिले हैं। इनमें गांव के मिश्रीलाल साह (52) उनकी पत्नी रेणु देवी उम्र (44), बेटी रोशन कुमारी (15) बेटा ललन कुमार (14) बेटी फुल कुमारी (8) शामिल हैं।

सन्न कर देने वाला था नजारा- पड़ोसियों ने बताया कि घर पिछले कुछ दिनों से बंद था। घर के सदस्य किसी को बाहर नहीं दिखे थे, जब आसपास के लोगों को बदबू महसूस हुई तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर देखा तो एक साथ पांच लोग फांसी पर लटके थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फांसी पर लटके सभी ने नए कपड़े पहन रखे थे।

समाज से कटा रहता था परिवार

सुपौल के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि मिश्रीलाल साह के पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार सामाजिक रूप से शाह का परिवार अपने भाइयों एवं समस्त ग्रामीणों से संपर्क नहीं रखता था। साह का परिवार आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं था। कुछ दिन पहले ही मिश्रीलाल साह की एक बेटी ने भागकर शादी कर ली थी, जिसके बाद परिवार अंतर्मुखी हो गया था।

मुंह पर कपड़ा लगाए घर के अंदर झांकते रहे लोग- एक घर के अंदर से कई दिनों से परिवार का कोई सदस्य नहीं निकल रहा था पर किसी ने उनकी सुध लेने की नहीं सोची। मरने वालों में 15, 14 और आठ साल के बच्चे भी थे, ऐसे में उनका घर से बाहर न निकलना कई शंकाओं को जन्म देता है। स्थानीय लोगों से संबंध न रखने के कारण किसी ने भी इतने दिनों तक साह परिवार के हाल-खबर लेने की नहीं सोची। गंध इतनी आई की घर के अंदर जाना ही पड़ा। बड़ी संख्या में लोग जुटे पर बदबू से परेशान होकर मुंह पर कपड़ा लगाना पड़ा। हालांकि पड़ोसियों का ये भी कहना है कि साह का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, ऐसे में मौत का कारण ये भी हो सकता है।

बसपा ने मांगे दावेदारों के नाम, कानपुर में उतारी सेक्टर प्रभारियों की फौज

कानपुर । जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी दलों ने उम्मीदवारों के नाम तय करने शुरू कर दिए हैं। बसपा ने के मुख्य सेक्टर प्रभारी मुनकाद अली ने दावेदारों के नाम मांग लिए हैं और कानपुर मंडल में एक- एक सीट जीतने के लिए मुख्य सेक्टर प्रभारियों की फौज उतार दी है। स्थिति यह है कि पार्टी अब उन्हें उम्मीदवार बनाने की सोच रही है जिनकी छवि समाज में अच्छी हो और वे पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे हों। ऐसे लोग जो हाल ही में दूसरे दलों से आए हैं शायद ही पार्टी उनके नाम पर विचार करे। पार्टी चाहती है कि हर जिले में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बने। इसके लिए भाईचारा कमेटियों को भी सक्रिय किया गया है।

बसपा 2001 में जिला पंचायत अध्यक्ष पद जीत चुकी है। तब पार्टी नेता मीरा संखवार अध्यक्ष बनीं थीं। इसके बाद बसपा ने इस सीट पर 2011 में इस सीट पर कब्जा किया और रीता कुशवाहा के सिर ताज सजा, लेकिन पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों की दगाबाजी के कारण ही पार्टी को 2012 में यह पद गंवाना पड़ा, क्योंकि सपा के देवेंद्र कटियार द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बसपा के जिला पंचायत सदस्यों ने भी वोट किया और रीता कुशवाहा को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा।

देवेंद्र कटियार अध्यक्ष बन गए। इसके बाद के चुनाव में भी सपा जीती और यहां से पुष्पा कटियार अध्यक्ष बनीं। बसपा 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बुरी तरह हारी।

अब 2022 में चुनाव होना है और बसपा की कोशिश है कि इस बार सूबे की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। इसीलिए पार्टी जिला पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना चाहती है। इसीलिए पार्टी ने जिलावार दो- दो मुख्य सेक्टर प्रभारी तैनात कर दिए हैं। अब सेक्टर प्रभारी ही दावेदारों की स्क्रीनिंग करेंगे और फिर प्रदेश मुख्यालय से प्रत्याशियों के नाम का एलान किया जाएगा। दावेदारों के नाम फाइनल करने की जिम्मेदारी मुख्य सेक्टर प्रभारी मुनकाद अली, बौद्ध प्रिय गौतम, प्रवेश कुरील, राजकुमार कप्तान, दीप सिंह, डीआर त्यागी के साथ जिला अध्यक्ष राम शंकर कुरील, मोहन मिश्रा जिला उपाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष रामनारायण निषाद को दी गई है।

यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सम्मानित किये जाएंगे प्रेरक स्टूडेंट्स, प्रेरणा लक्ष्य एप के जरिये होगा सेलेक्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे अपनी कक्षा के हिंदी और गणित विषयों के अनुरूप प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे, उन्हें प्रेरक बालक/बालिका के रूप में चिह्नित किया जाएगा। प्रेरणा लक्ष्य एप के माध्यम से ऐसे बच्चों का आकलन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी डायट प्राचार्यों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है।

प्रेरक बालिक/बालिका के लिए बच्चों का आकलन डायट के डीएलएड प्रशिक्षु, डायट मेंटर तथा ब्लॉक के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन करेंगे, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह आकलन महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को किया जाएगा। यदि किसी वजह से शनिवार को अवकाश है तो उससे पहले वाले कार्यदिवस में यह आकलन किया जाएगा। बच्चों के आकलन के लिए हर तिमाही के लिए डायट प्राचार्य रोस्टर तैयार करेंगे। तिमाही की गणना एक अप्रैल, 2021 से की जाएगी। डायट प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि आकलन से कम से कम एक हफ्ता पहले स्कूल को इसकी सूचना दे दी जाए।

प्रेरणा लक्ष्य एप पर आकलन के लिए किसी भी स्कूल के कक्षा एक से पांच तक के बच्चे खुद को नामांकित कर सकते हैं या प्रधानाध्यापक शिक्षकों की मदद से उन बच्चों की सूची बना सकते हैं जिनका प्रदर्शन प्रेरणा लक्ष्यों के अनुरूप है। आकलनकर्ता अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से नामांकित बच्चों का आकलन करेगा। बच्चों द्वारा बताये गए उत्तर को प्रेरणा लक्ष्य एप पर दर्ज किया जाएगा।

उत्तरों को दर्ज करने के बाद प्रेरणा लक्ष्य एप पर अपने आप बच्चों के रिजल्ट आ जाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि बच्चे को प्रेरक बालक/बालिका घोषित किया जा सकता है। हर तिमाही के आखिरी हफ्ते में स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति मिलकर प्रेरक सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे, जिसमें बच्चों के अभिभावकों व समुदाय के गण्यमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाएगा।

प्रयागराज में %शनि अमावस्या% के अवसर पर संगम पर स्नान करने के बाद भक्त।

एक नजर

कर्नाटक में फिर सख्त हुए कोरोना नियम, अब सिर्फ इतने लोग शादी समारोह में हो सकेंगे शामिल

बेंगलुरु । देश में कोरोना वायरस के मामतों में एक बार फिर तेजा आ रही है। राज्य में बढ़तो मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को विवाह जैसे आयोजनों और समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर का कहना है कि कोरोना के नए मामलों में बढ़ोत्तरी और एक दूसरी लहर के डर के बीच इन उपायों को किया जा रहा है। नए नियमों के अनुसार, खुले स्थानों में आयोजित किए जाने वाले विवाह या अन्य आयोजन में अब केवल 500 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जबकि हॉल या बंद स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों में लोगों की संख्या को 200 कर दिया गया है।

वहीं, जन्मदिन समारोह के लिए खुले में 100 लोगों और बंद स्थानों में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अंतिम संस्कार के समय भी संख्या में लोगों को अनुमति दी जाएगी। हालांकि, दाह संस्कार और दफन करने के समय केवल 50 लोग ही होंगे अनुमति होगी। खुले स्थानों में धार्मिक और राजनीतिक समारोहों के लिए लोगों की संख्या 500 तक सीमित कर दी गई है। कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कुछ जिलों में परिक्षण को बढ़ाया गया है। बेलगावी में रोजाना 4,000 परिक्षण, बेंगलुरु और बीबीएमपी में 40,000 परिक्षण प्रति दिन, दक्षिण कन्नड़ में 3,000 परिक्षण रोजाना और मैसूरु में रोजाना 5,000 परिक्षण किया जाएगा। देश में शनिवार को कोरोना वायरस के 24,882 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में अबतक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,13,33,728 हो गई है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में रोजाना मामलों में बढ़ोतरी हो रहा है।

ओडिशा में 700 जगहों पर जल रहा जंगल, सिमलीपाल में 9 जगहों पर लगी है आग; बारिश ने दी बड़ी राहत

भुवनेश्वर । जंगल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है।ओड्राफ एवं दमकल विभाग टीम को आग बुझाने के लिए नियोजित किया गया है। शुक्रवार को राज्य में 700 जगहों पर जंगल जलने की जानकारी टास्क फोर्स के मुख्य संदीप त्रिपाठी ने दी है। मालकानगिरी, गंजाम, बलांगीर तथा बौद्ध में मौजूद जंगल में लगी आग अभी भी बढ़ रही है। सिमलीपाल में वर्तमान समय में 9 जगहों पर आग लगी है।

जानकारी के मुताबिक शनिवार पूर्वाह्न एवं शुक्रवार अपराह्न को सिमलीपाल के आस-पास क्षेत्र हल्की बारिश हुई है। इसके प्रभाव से सिमलीपाल इलाके में लगने वाली शुक्रवार दो सदस्यीय केन्द्रीय प्रतिनिधि एनटीसीए के आईजी डा. अमित मलिक तथा भुवनेश्वर में अवस्थापित केन्द्रीय पर्यावरण जंगल मंत्रालय के उप महानिदेशक सुब्रत महापात्र ने सिमलीपाल के मध्य स्थित उपरवाराहामुडा में एसटीआर के अधिकारियों के साथ सिमलीपाल जंगल में लगी आग के कारण एवं किस प्रकार से आग को बुझाया जाए, उस पर चर्चा की है। इसके साथ ही शिमिलीपाल अभयारण्य में रहने वाले लोगों के साथ सिमलीपाल में लगी आग के कारण के बारे में चर्चा किए हैं। इस आग से कितना नुकसान हुआ है, उसका भी अनुध्यान किया जा रहा है। अनुध्यान करने के बाद यह टीम राज्य सरकार एवं टास्क फोर्स कमेटी को सलाह देने की बात जानने में आयी है। गौरतलब है कि प्रदेश के साथ जिले विभिन्न क्षेत्र में आसमान में बादल छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को नअणा में 6.8 मिमी. पोडाडिहा में 0.762 मिमी., भजवसा में 7.62 मिमी., उपरवाराह कामुडा में 3.2 मिमी., जेनाबिल में 6.350 मिमी. कबाटघाइ में 1.778 मिमी. चहला में 0.8 मिमी. वरेहिपाणी में 1.778 मिमी. बारिश रिकार्ड की गई है। फारेस्ट आईटी एवं जीओमेटिक सेंटर द्वारा प्रतिदिन उपग्रह से एफएसआई के माध्यम से मिले तथ्य के मुताबिक बीट स्तर पर कर्मचारियों के पास भेजकर वहां आग बुझाने के कार्य को त्वरान्वित किया जा रहा है। 95 प्रतिशत जगहों पर आग बुझ गई है। सिमलीपाल में आग लगने से मणदा वन क्षेत्र के दो हिरण बाहर आने की बात पता चली है। वहीं दूसरी तरफ सिमलीपाल अभयारण्य में लगी आग पर विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक ने नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि शिमिलीपाल देश का सबसे बड़ा जैव मंडल है। राज्य सरकार तुरन्त राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद विभिन्न विशेषज्ञों से सलाह लें। जिस जंगल में आग लगी है, उस इलाके के स्थानीय जन प्रतिनधियों को भी मुहिम में शामिल किया जाए। स्थानीय लोगों की सहभागिता से ही जंगल की सुरक्षा हो पाएगी, सरकार को इसे नहीं भूलना चाहिए।

पीरजादा की पार्टी को नहीं मिल रहे प्रत्याशी, 30 के बदले अब 26 सीटों पर ही लड़ेगी

कोलकाता । वाममोर्चा-कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में उतरने को ताल ठोंक रहे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट (आइएसएफ) को चुनाव लडने् के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। काफी जद्दोजहद के बाद तीस के स्थान पर अब 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब्बास ने तो 50 से अधिक सीटें वाम-कांग्रेस गठबंधन से मागी थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले तक अब्बास सिद्दीकी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दंभ भर रहे थे। कांग्रेस के साथ इस कारण काफी दिनों तक सीटों के बंटवारे को लेकर मामला भी फंसा था। बाद में कांग्रेस भी सात सीटें छोड़ दी थी। अब जब अब्बास की झोली में 30 सीटें आई तो उसे उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का अंतिम दिन नजदीक आने के कारण चार सीटों पर वाममोर्चा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं।

गौरतलब है कि आइएसएफ ने पिछले दिनों कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई गठबंधन की रैली में भारी भीड़ जुटाकर बंगाल से ममता सरकार का सफाया करने का दावा किया था। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के गठन में ज्यादा समय नहीं हुआ है इसलिए वह खुद को सांगठनिक तौर पर अभी मजबूत नहीं कर पाई है इसलिए उसे इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी बंगाल को लेकर जितनी बातें कर रहे थे पहले दो चरणों में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं।

जोधपुर एनएच-11 पर बस और ट्रेलर ट्रक की जोरदार टक्कर, 5 की मौत 12 घायल; बस के उड़े परखच्चे

जोधपुर । जोधपुर जिले के फलोदी बाप मार्ग पर शनिवार सवेरे एक बड़ा हादसा हो गया। बाप थाना क्षेत्र के गड़ाना गांव के निकट एक ट्रोले और मिनी टूरिस्ट बस की आमने-सामने की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ले जाया गया है। जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दुख व्यक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर शनिवार सवेरे एक मिनी टूरिस्ट बस (टेम्पो ट्रेवल बस) जैसलमेर की ओर जा रही थी, जो कि सामने से आ रहे एक ट्रोले से जा भिड़ी। ट्रेलर और निजी बस में आमने-सामने भिड़ंत घटना में 3 पुरूष व 2 महिलाओं सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गयी। वहीं 12 लोग इस दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। जिसके बाद एक बारगी हाइवे पर चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर बाप थानाधिकारी हरिसिंह राजपुरोहित सहित अन्य स्टाफ गड़ाना गांव पहुचा। इसके बाद एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुचाया गया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को बीकानेर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं वहीं घायलों में 6 बच्चे भी शामिल है। सभी लोग रामदेवरा दर्शनों के बाद जैसलमेर की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। मृतकों के शिनाख्ती के प्रयास जारी है। इधर घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवत ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

टूरिस्ट बस के उड़ गए परखच्चे

फलोदी और बाप के बीज गाड़ाना गांव के समीप हुई इस दुर्घटना में टूरिस्ट बस के परखच्चे उड़ गए। टूरिस्ट बस में कुल 17 लोग सवार थे वही ट्रोले में लोहे के बड़े पाइप भरे हुए थे।

टक्कर इतनी भयंकर थी के टूरिस्ट बस के भीतर बैठे लोग इसमें बुरी तरह फंस गए थे। जिसके बाद स्थानीय निवासियों और 108 एंबुलेंस सेवा के स्टाफ ने पुलिस की मदद से सभी को बाहर निकाला। थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दिल्ली से यह पर्यटक मिनी बस से जैसलमेर जा रहे थे, तभी आज सुबह बस फलौदी के बाप थाना इलाके के समीप ये हादसा हो गया। यह सभी दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं तथा रामदेवरा जैसलमेर घूमने जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था बहाल करवाई। पुलिस मृतकों के शिनाख्त और परिवार से संपर्क में जुटी है।

मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री ने दुख जताते हुए कहा - जोधपुर में फलोदी में हुए सड़क हादसे की जानकारी मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जोधपुर के सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दुख जताया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और दुख की इस घड़ी में परिवार को संभल व्यक्त किया है। एनएच

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना जाहिर करते हुए कहा- जोधपुर के बाप क्षेत्र में गाड़ना गांव के पास एनएच - 11 पर हुए सड़क हादसे में पांच लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है । मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं , ईश्वर उन्हें इस बेहद कठिन समय में सम्बल दें , दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें । घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है ।

केरल सरकार को झटका, विधायकों के खिलाफ केस वापस नहीं होंगे

कोच्चि । केरल विधानसभा चुनाव से पहले विजयन सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2015 में विधानसभा में हंगामा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में वामदल के छह विधायकों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।

राज्य सरकार ने तिरुअनंतपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।

सीजेएम की अदालत ने इन विधायकों के खिलाफ न सिर्फ केस वापस लेने की मांग ठुकरा दी थी, बल्कि सभी से सुनवाई का सामना करने को भी कहा था। आरोपितों में उद्योग मंत्री ईपी जयराजन और उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील भी शामिल हैं।

वामपंथी पार्टी तब विपक्ष में थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अगले वित्त वर्ष के लिए सदन में बजट पेश कर रहे थे, तब इन विधायकों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की थी, जिसमें सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था।

बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का एलान किया था। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं।

निवर्तमान विधानसभा में आठ महिला विधायक हैं और बाकी 132 पुरुष विधायक हैं। 1 जून, 2021 को केरल सरकार का कार्यकाल समाप्त होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा ने बताया केरल में पहले 21,498 चुनाव केंद्र थे, अब यहां चुनाव केंद्रों की संख्या 40,771 होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा ने बताया कि केरल में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। राज्य की 140 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। 2 मई को मतगणना होगी।

कोरोना महामारी के खिलाफ साथ आए भारत-अमेरिका, 2022 तक 100 करोड़ वैक्सीन बनाने में करेगा मदद

नई दिल्ली । कोरोना महामारी की चुनौती के खिलाफ क्वाड देश साथ आए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर वैक्सीन निर्माण की क्षमता बढ़ाने को लेकर भारत और अमेरिका साथ आए हैं। अमेरिका, भारत को साल 2022 के अंत तक कोरोना वायरस की 100 करोड़ वैक्सीन बनाने में मदद करेगा।अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, भारतीय निर्माता जैविक ई लिमिटेड को 100 करोड़ वैक्सीन का निर्माण करने में सहायता करेगी। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम 2022 के अंत तक कोविड-19 टीकों की कम से कम 100 करोड़ डोज का उत्पादन करने के अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए भारतीय निर्माता जैविक ई लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी।

शुक्रवार को क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया की एक अहम बैठक हुई। इस अहम बैठक में कोरोना वायरस से जंग लड़ रही दुनिया को इससे निजात दिलाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें एक बड़ा फैसला ये रहा कि अमेरिकी वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन का उत्पादन भारत में किया जाएगा। इसके साथ ही एक साल के अंदर एशियाई देशों को वैक्सीन पहुंचाने का फैसला भी इस बैठक में लिया गया। क्वाड देशों की बैठक में भारत की वैक्सीन कूटनीति को आगे बढ़ाने के साथ इसका समर्थन करने का भी फैसला लिया गया। देश में अमेरिका के टीके बनाने के लिए भारत अपनी विनिर्माण क्षमता का उपयोग करेगा।

शुक्रवार को 'क्वाड' के डिजिटल तरीके से आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस सकारात्मक दृष्टिकोण को भारत के 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन के विस्तार के तौर पर देखता हूं, जो कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है।

मणिपुर सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने कहा- प्रदेश में म्यांमार निवासियों के आने की नहीं कोई जानकारी

इंफाल । मणिपुर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक उनके राज्य में म्यांमार के निवासियों के आने की कोई खबर नहीं है। सीएम एन. बीरेन सिंह ने कहा कि हमने सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और सभी सतर्क कर दिया है। साथ ही कहा कि हालांकि, यह मामला एक द्विपक्षीय मुद्दा है (भारत और म्यांमार के बीच) और राज्य सरकार इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

इन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है

बता दें कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के शिकार शरणार्थियों के भारत शरण लेने के मुद्दे पर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के चार राज्यों मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ-साथ असम राइफल्स को सैन्य तख्तापलट के शिकार म्यांमार से शरणार्थियों के आगमन पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। बता दें कि उक्त चारों राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है।

बता दें कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग तख्तापलट को लेकर काफी नाराज हैं। सेना इन विरोध प्रदर्शनों पर लगाम लगाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की भी कई घटनाएं पिछले दिनों सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विरोध प्रदर्शनों में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में म्यांमार के कुछ लोग भारत में भी शरण लेने की योजना बना सकते है। इसलिए भारत ने संबंधित राज्यों को सर्तक कर दिया है।

अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग महिला पर गिरा छत का पंखा, हालत गंभीर; आइसीयू में भर्ती

कटक । कटक बड़ा मेडिकल में एक बुजुर्ग महिला मरीज के ऊपर सीलिंग फैन (छत का पंखा) गिर जाने की घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में आयोग के समक्ष आने वाले आरोप पर सुनवाई करते हुए राज्य स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के सचिव को ठोस कदम उठाने के लिए निर्देश जारी किया है।

निर्देश के मुताबिक आगामी 8 सप्ताह के अंदर इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव को उपयुक्त कदम उठाना है। उन्होंने क्या ठोस कदम उठाया है उस संबंध में भी स्वास्थ्य सचिव की ओर से आयोग में आरोप लाने वाले व्यक्ति और पीड़िता को अवगत कराया जाना है, यह निर्देश भी जारी किया है आयोग ने। हिमांशु शेखर नायक के आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए आयोग ने यह निर्देश दिया है।

विदित है कि, एससीबी मेडिकल सर्जरी विभाग बर्न वार्ड में बेड की कमी के चलते नीचे चटाई पर इलाज करवाने वाली जाजपुर की 78 वर्षीय पार्वती दास के ऊपर एक सीलिंग पंखा अचानक गिर पड़ा। इसके चलते उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इस घटना में दूसरे मरीज भी सामान्य तौर पर घायल हुए। घटना के संबंध में मेडिकल के अधीक्षक के पास पीड़ित महिला के बेटे प्रशांत दास ने शिकायत की।

यहां तक कि पुलिस के पास भी पीड़ित महिला के परिवार वाले आरोप लाए थे, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। इससे पहले भी एससीबी मेडिकल में इस तरह की घटना कई बार घट चुकी है।

मरीजों के ऊपर पंखा गिरने की घटना को लेकर अतीत में कई बार चर्चा भी हुई है। हर बार समस्या के हल के लिए मेडिकल के अधिकारी निर्देश देकर चुप बैठ जाते हैं। लेकिन इस तरह की घटना का किसी भी तरह का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके चलते एससीबी में आने वाले मरीजों के रिश्तेदारों के बीच खासा असंतोष फैल रहा है।

इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ पीड़ित मरीजों को मदद पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास हिमांशु शेखर नायक ने आवेदन किया था।

अब ज्यादा मजबूत होगा हड्डी जोड़ने वाला इंप्लांट, देश में हुई मेडिकल क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण खोज

भोपाल । वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) के भोपाल स्थित प्रगत पदार्थ प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (एम्प्री) ने देश में पहली बार 3 डी मॉडल वाले इंप्लांट (हड्डी को जोड़ने के लिए विकल्प के तौर पर धातु से बनी रॉड, प्लेट या अन्य संरचना) बनाने की तकनीक विकसित की है। अब स्टील या टाइटेनियम के साथ सिर्फ एक फीसद कार्बन आधारित धातु ग्रैफीन मिलाकर इंप्लांट को 40 फीसद तक ज्यादा मजबूत बनाया जा सकेगा। यह इंप्लांट बिल्कुल हड्डी की तरह कार्य करेगा। अभी स्टील या टाइटेनियम से इंप्लांट बनाए जाते हैं। मजबूती बढ़ने का फायदा यह होगा कि इंप्लांट हल्के बनाए जा सकेंगे।

ग्रैफीन ज्यादा महंगी धातु नहीं है, इसलिए कीमत में भी कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह सर्जकिल उपकरण भी से बनाए जा सकेंगे।एम्प्री के प्रधान विज्ञानी डॉ. एन सतीश ने बताया कि बैक्टीरिया, वायरस और अन्य जीवाणुओं के लिए ग्रैफीन ब्लेड की तरह काम करता है। यह जीवाणु की ऊपरी दीवार को काट देता है, जिससे उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वह मर जाते हैं।

लिहाजा सर्जकिल उपकरण या इंप्लांट से संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। डॉ. एन सतीश ने बताया देश में कहीं भी इस तकनीक से इंप्लांट नहीं बनाए जा रहे हैं। दुनिया में अमेरिका और चीन ने तकनीक तो विकसित की है, पर व्यावसायिक उपयोग शुरू नहीं हुआ है।

अध्ययन के साथ किया निरंतर अभ्यासन मैसूर की पुरोहित भ्रमरंभा महेश्वरी ने बताया कि मंत्र पढ़ने से कोई पुरोहित नहीं बन जाता। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना एवं उसके अर्थ को जानना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए वेदों का संपूर्ण ज्ञान अर्जन एवं अध्ययन आवश्यक है। वेद को वैसे ही आध्यात्मिकता का मूल माना जाता है। वैदिक ज्ञान हमारे विचारों को खोलते हैं। उसे पंख देते हैं। जैसे, पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में सदियों से स्त्रियों को दोयम दर्जा दिया गया है। विवाह संस्कार में कन्यादान की रस्म इसका सूचक है। कन्या कोई वस्तु नहीं, जिसका दान किया जाये।

2015 से चल रही थी रिसर्च

ग्रैफीन आधारित 3 डी मॉडल बनाने के लिए एम्प्री में यहां के निदेशक डॉ. अवनीश कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शोध चल रहा था। नीदरलैंड के जर्नल च्मटेरियल्स टुडे केमेस्ट्रीच्च् में एम्प्री की इस तकनीक पर शोध पत्र प्रकाशित हो चुका है। एम्प्री की लैब में शोध के दौरान माइक्रोस्कोपिक और नैनो स्केल तरीके से देखा गया कि यह धातु दूसरी धातुओं से किस तरह बेहतर है। इसके बाद 3 डी मॉडल की तकनीक विकसित की गई। इसे एडिटिव मैनूफैक्चरिंग कहा जाता है। यह 3 डी प्रिंटिंग से आगे की तकनीक है।

एम्स के दंत चिकित्सा विभाग के एचओडी प्रो.(डॉ.) पंकज गोयल ने बताया कि दांत के जबड़े आदि के इलाज में अभी तक 3 डी प्रिंटिंग (इमेज) का उपयोग करते थे। एम्प्री ने 3 डी मॉडल विकसित किया है। इसमें हड्डी के जितने हिस्से को बदला जाना है उसका 3 डी मॉडल बनाया जाएगा। मॉडल बनाने के लिए सीटी स्कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। उस हिस्से की पहले 3 डी सीटी स्कैन से फोटो की तरह एक नेगेटिव इमेज बनाई जाएगी। इसके बाद इस इमेज के अनुरूप 3 डी मॉडल इंप्लांट लगाया जा सकेगा। इस तकनीक के इस्तेमाल को लेकर एम्स भोपाल में शनिवार को एक कार्यशाला होने जा रही है। इसमें हृदय रोग, हड्डी रोग, दंत रोग और न्यूरोलाजी विभाग के चिकित्सक शामिल होंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तकनीक के उपयोग को लेकर एम्प्री और एम्स के बीच शनिवार को एक एमओयू भी होने जा रहा है।

एम्प्री के प्रधान विज्ञानी डॉ. एन सतीश ने कहा कि तकनीक विकसित करने के बाद अब इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए कंपनियों की तलाश की जा रही है। कंपनी मिलने के बाद पेटेंट के लिए भी जल्द आवेदन किया जाएगा। फिर ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा।

देश में फिर लौटने लगा लॉकडाउन! महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू; स्कूल-कॉलेज बंद

नई दिल्ली, एजेंसियां । देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। हर तरफ के उपायों के बाद भी कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। देश में लगभग ढाई महीने बाद एक दिन में 24 हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में इस साल मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। महराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे है। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हो रही है। नागपुर और परभणी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में भी नए मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं, पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है।

महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते औरंगाबाद, नागपुर, परभणी और पुणे में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के दौरान 15 हजार से अधिक नए केस मिले है। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर पूरी तरह लॉकडाउन लगाया दिया गया है। नागपुर में 15 से 21 मार्च के बीच लाकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान निजी कार्यालय बंद रहेंगे जबकि सरकारी दफ्तरों में 25 प्रतिशत कर्मियों के साथ कामकाज होगा। जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।

पंजाब में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। 13 मार्च से ये आदेश लागू होगा। इस दौरान 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों बंद रहेंगे। दूसरी तरफ लुधियाना, पटियाला, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब सहित आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इन दोनों राज्य के कई जिलों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी कआ रही है। इसके मद्देनजर रविवार या सोमवार से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। उन्होंने राज्य में कोरोना वायरस स्थिति की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार शाम आयोजित एक बैठक के दौरान यह बात कही।

दिल्ली में मिला दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन का मरीज

राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 431 नए मामले आए हैं। इससे पहले एक दिन में 409 मामले मिले थे। शुक्रवार को दिल्ली में दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वायरस के स्ट्रेन का संदिग्ध मरीज मिला। मरीज का लोकनायक अस्पताल में इलाज चल रहा है। केरल का रहने वाला 35 वर्षीय संदिग्ध मरीज बुधवार को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) लैब भेजा गया है।

असम के कामरूप जिले के बहैत में सुरक्षा कर्मियों ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक वाहन की जाँच करते हुए।

अनुष्का शर्मा

और विराट कोहली की प्यारी सी तस्वीर हुई वायरल, एक घंटे में ही मिले 23 लाख लाइक्स

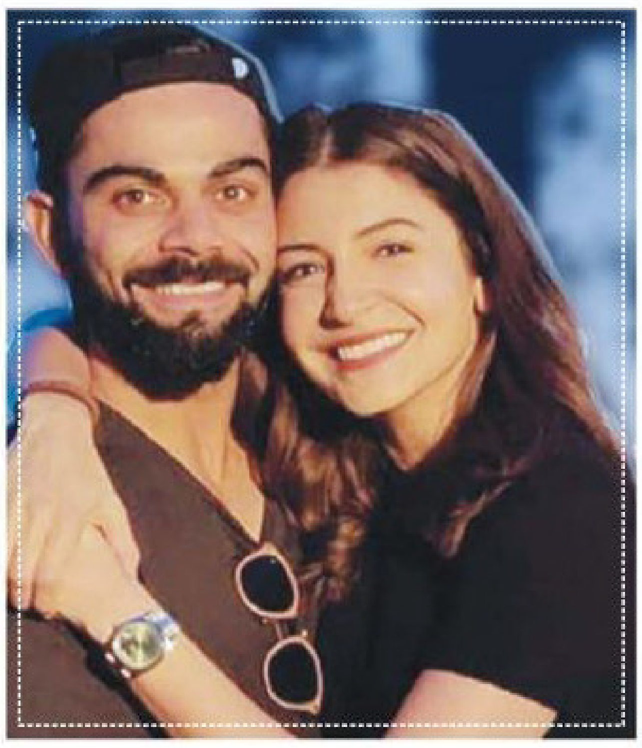

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और टीम इंडिया के कैप्टेन विराट कोहली (Virat Kohli) की बेटी वामिका आज पूरे दो महीने की हो गई हैं. अनुष्का ने अपने इंस्टा स्टोरी में जहां एक केक में लगे 2 कैंडल की फोटो शेयर की, तो वहीं अभी एक घंटे पहले विराट ने अनुष्का के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

इंस्टाग्राम पर एक घंटे के अंदर विराट द्वारा शेयर की गई तस्वीर को 23 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है.साथ लोग विराट और अनुष्का शर्मा की फोटो पर लगातार कमेंट्स कर दोनों की तस्वीर की काफी तारीफ भी कर रहे हैं. बता दें, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Womens Day) के मौके पर अनुष्का ने अपनी बेटी के साथ एक फोटो शेयर की थी.

वहीं, विराट कोहली ने भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका की फोटो शेयर करते हुए अनुष्का को सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक बताया था.बता दें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 11 जनवरी को एक बेटी के पैरेंट्स बने थे. विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी थी.अनुष्का और विराट दोनों ही इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन दोनों तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

अनुष्का और विराट दोनों की सोशल मीडिया पर भी लंबी चौथी फैन फॉओवर्स की लिस्ट है. अनुष्का को जहां इंस्टाग्राम पर 46.6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, तो वहीं विराट को इंस्टा पर फॉलो करने वालों की संख्या 102 मिलियन है.

इंडियन आइडल 12 में टाइगर श्रॉफ ने कह दी कुछ ऐसी बात, जिसे सुनकर रोने लगे जैकी श्रॉफ

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) हाल ही में सिंगिंग रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) में पहुंचे। शो में जैकी श्रॉफ के साथ ही कार्यक्रम के कंटेस्टेंट्स, जजेस और होस्ट ने खूब मस्ती की। वहीं जैकी ने भी अपनी जिंदगी की कई बातों को साझा किया। हालांकि इस दौरान शो में कुछ ऐसा भी हुआ, जिसे देखकर जैकी श्रॉफ भावुक हो गए और रोने लगे।

जैकी को फैमिली का स्पेशल मैसेज

दरअसल शो में कुछ कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस के बाद जैकी श्रॉफ को एक वीडियो दिखाया जाता है। इस वीडियो में जैकी श्रॉफ के लिए उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ (Ayesha Shroff) और बेटे टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) का स्पेशल वीडियो मैसेज होता है। एक ओर जहां आयशा अपनी कुछ यादों को साझा करती हैं तो वहीं टाइगर अपने पिता को गर्व महसूस करवाने की बात कहते हैं।

आयशा और जैकी की पहली मुलाकात

वीडियो में आयशा कहती हैं, आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं पहली बार जैकी श्रॉफ से मिली थी, तब मैं 13 साल की थी। असल में हम एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर मिले थे, जहां हमने 2 मिनट बात की और फिर मैंने घर आकर अपनी मां से कहा कि मैं एक ऐसे आदमी से मिली, जिससे मैं शादी करूंगी।

तीन साल बाद बातचीत हुई शुरू

वीडियो में आयशा आगे कहती हैं, इस मुलाकात के तीन साल बाद मैंने फिर उन्हें देखा और फिर हमारे बीच बातचीत की शुरुआत हुई। हम अक्सर बाहर भी जाते थे। उनसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया फैसला है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे उनके जैसा बढ़िया आदमी मिला। वो इस दुनिया के सबसे अच्छे पति और सबसे अच्छे पिता हैं।

टाइगर का मैसेज

आयशा के बाद जग्गू दादा के बेटे टाइगर श्रॉफ का भी वीडियो मैसेज दिखाया जाता है। वीडियो में टाइगर कहते हैं, सबसे पहले तो मैं सभी कंटेस्टेंट्स को उनके भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। सभी जजों को मेरा नमस्कार। मुझे यकीन है कि हमारी फैमिली ने आपको हमारे बारे में काफी कुछ बता दिया होगा।

भावुक हुए जैकी

टाइगर वीडियो में आगे कहते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आई लव यू वेरी मच डैड! जिंदगी में मेरा एक ही मकसद है कि मैं हर दिन आपको गर्व महसूस कराऊं और मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूं। बेटे का वीडियो देख जैकी भावुक हो जाते हैं और इंडियन आइडल को इसके लिए धन्यवाद देते हैं।

Kangana Ranaut ने जमानती वारंट को कोर्ट में दी चुनौती, 15 मार्च को होगी सुनवाई

गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि की शिकायत के संबंध में बॉलीवुड एक अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था. मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जमानती वारंट को कंगना ने सत्र अदालत में चुनौती दी है. कंगना के वकील ने कहा कि बुधवार को दाखिल उनकी याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई होनी है.

अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक मार्च को कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. इससे पहले वह अदालत में पेश नहीं हुई थीं. मजिस्ट्रेट आर आर खन्हड ने फरवरी में उन्हें समन जारी किया था.जब कंगना अदालत में पेश नहीं हुई तो अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और मामले में सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर की. मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंगना को समन को चुनौती देने के लिए किसी ऊंची अदालत में जाने की स्वतंत्रता है लेकिन वह इस अदालत में पेश होने से नहीं बच सकतीं.

सोमवार को होगी सुनवाई

इससे पहले पुलिस ने अख्तर की शिकायत पर एक रिपोर्ट जमा की थी जिसमें कहा गया था कि कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का अपराध बनता है. अख्तर ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर उनके बारे में झूठे बयान देने तथा उनकी साख को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया.

कंगना ने पिछले साल जून में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में एक गुट होने की बात कही थी. कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि सत्र अदालत में उनकी अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी.

स्टेज पर फूट फूट कर रोई थीं Best TV Actress का अवॉर्ड लेने पहुंचीं

हिना खान

शो के होस्ट भी करने लगे थे नकल

हिना खान(Hina Khan) आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है. आज बच्चा बच्चा उन्हें जानता है लेकिन ये सब हिना को रातों रात नहीं मिला था बल्कि इस स्टारडम के पीछे उनकी सालों की मेहनत थी जिसका फल उन्हें बखूबी मिला. हिना ने बतौर एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की थी स्टार प्लस के सबसे फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है(Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) से. जिसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था. वहीं एक बार उन्हें इस रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला तो वो स्टेज पर फूट फूट कर रोने लगी थीं.

शो में निभाया था अक्षरा का पॉपुलर रोल

ये रिश्ता क्या कहलाता है में हिना खान ने अक्षरा नाम की लड़की का किरदार निभाया था जो काफी पॉपुलर हुआ. यही कारण था कि इस किरदार के लिए उन्हें आईटीए का बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था. जब हिना खान इस सम्मान को लेकर स्टेज पर पहुंचीं तो हाथों में ट्रॉफी लेकर काफी खुश हुईं लेकिन उसके साथ ही ये क्षण उनके लिए बेहद खास था इसलिए वो भावुक हो गईं. वो अपने इमोशन्स पर काबू नहीं कर पाईं और स्टेज पर ही काफी रोने लगीं.

होस्ट भी करने लगे थे नकल

वहीं जब अक्षरा यानि हिना खान स्टेज से चली गईं तो शो के होस्ट सुनील ग्रोवर भी उनकी नकल करने लगे और उन्ही की तरह रोने की एक्टिंग करने लगे थे.वहीं फिलहाल हिना खान इस शो को अलविदा कह चुकी हैं अब वो काफी सालों से शो से दूर हैं लेकिन बिग बॉस में नज़र आने के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख चुकी हैं. वो हैक्ड नाम की फिल्म में नज़र आई थीं. जो साइबर क्राइम पर आधारित थी. इस फिल्म में हिना का रोल काफी डिफरेंट था और उन्हें काफी पसंद भी किया गया.

दूसरे टी20 में इंग्लैंड को हराकर बराबरी के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम

अहमदाबाद, (एजेंसी)। भारतीय टीम रविवार को यहां दूसरे टी20 क्रिकेट मुकाबले में मेहमान टीम इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी के इरादे से उतरेगी। पहले टी20 मैच में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम पहले टी20 में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनो में नाकाम रही थी जिससे अब उसपर बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा। पहले मैच में श्रेयस अय्यर को छोड़कर अन्य सभी बल्लेबाज रन नहीं बना पाये। गेंदबाजी में भी भारतीय टीम सामान्य रही जिससे मैच उसके हाथ से निकल गया। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और लोकेश राहुल का जो प्रयोग कप्तान विराट कोहली ने किया था वह नाकाम रहा। रोहित शर्मा का पहले टी20 में भारतीय टीम ने आराम दिया था पर मैच के दौरान लगातार रोहित की कमी नजर आई। इयान मोर्गन की कप्तानी में मेहमान टीम ने भारतीय टीम को हर क्षेत्र में शिकस्त दी। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार भारतीय टीम ने शुरूआती हार के बाद वापसी की है उससे प्रशंसकों को उम्मीद है कि टीम इस मैच में भी वापसी करेगी। पहले मैच में ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या अच्छी शुरूआत के बाद भी बड़ी पारियां नहीं खेल पाये थे, ऐसे में प्रशंसकों को अब इन दोनो से ही बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। पंड्या और ऋषभ विकेट की रफ्तार को भांप नहीं सके और गेंद को मिल रही अतिरिक्त उछाल का सामना नहीं कर पाए। कप्तान विराट भी पहले मैच में खाता नहीं खोल पाये थे अब दूसरे मैच में उनपर भी बड़ी पारी खेलने का दबाव रहेगा। कोहली ने मैच के बाद कहा था कि इस विकेट पर मनचाहे शॉट नहीं खेल सके। श्रेयस की पारी से दिखा कि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कैसे करना है और उछाल से कैसे निपटना है। वहीं बाकी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सके। हमने खराब बल्लेबाजी थी और जिससे मैच हमारे हाथ से निकल गया। दूसरे मैच में बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को अवसर मिला सकता है। अनुभवी खिलाड़ी धवन लगातार खराब फॉर्म के से गुजर रहे हैं वह पहले मैच में चार रन ही बना सके। वहीं गेंदबाजों के पास बचाव के लिए अवसर ही नहीं था क्योंकि भारतीय बल्लेकबाजों ने पर्याप्त रन नहीं बनाये थे। पहले मैच में केवल एक विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल की जगह कल पर दूसरे मैच में ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को अंतिम ग्यारह में जगह मिल सकती है। तेवतिया आक्रामक बल्लेबाज होने के साथ ही गेंदबाजी भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मेहमान टीम इस मैच में बढ़ हुए मनोबल के साथ उतरेगी है। उसके बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने पहले मैच में उम्मीद के अनुसार बेहतर प्रदर्शन किया था। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस मैच में भी उम्मीद के अनुसार बेहतर गेंदबाजी के इरादे से उतरेंगे।

दोनो टीमें इस प्रकार हैः

भारतः विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शारदुल ठाकुर, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, राहुल तेवतिया, इशान किशन (रिजर्व विकेटकीपर)।

इंग्लैंडः इयान मोर्गन (कप्तान), जोस बटलर, जेसन रॉय, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, बेन स्टोक्स, मोईन अली, आदिल राशिद, रीस टॉपले, क्रिस जोर्डन, मार्क वुड, सैम कुरेन, टॉम कुरेन, सैम बिलिंग्स, जॉनी बेयरस्टो और जोफ्रा आर्चर।

कतर में महिलाओं के सेमीफाइनल मुकाबले में खेलती हुई जापान की इटो मीमा।

पोंटे वेड्रा बीच में प्लेयर्स चैम्पियनशिप गोल्फ में खेलते हुए ब्रेयसन।

टीम का बल्लेबाजी का तरीका नहीं बदलेगा : अय्यर

अहमदाबाद, (एजेंसी)। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कहा है कि टीम की बल्लेबाजी का तरीका आक्रामक ही बना रहेगा हालांकि अगले मैच में टीम को बेहतर तरीक से अपनी रणनीति पर काम करना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में भारतीय टीम केवल 124 रन ही बना पायी थी। इसके बाद मेहमान टीम इंग्लैंड ने चार ओवर और तीन गेंद बाकी रहते ही आसानी से लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।

वहीं सीरीज में 1- 0 से पीछे होने पर हर हालात में शॉट्स खेलने का भारतीय टीम का यह नया बल्लेबाजी का अंदाज क्या अब बदलेगा। इसपर अय्यर ने कहा कि नहीं क्योंकि हमारे पास निचले क्रम तक पावर हिटर्स हैं और इस रवैये में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। हमने एक रणनीति बनाई थी जिस पर अमल जरूरी था क्योंकि हमें बेहतर संयोजन के लिए विश्व कप से पहले सारे दांव आजमाने हैं। यह पांच मैचों की श्रृंखला है और इसमें प्रयोग करके देख सकते हैं कि क्या सही लगता है। यह पूछने पर कि क्या उन पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव है, अय्यर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुलकर खेल रहा हूं और अपनी पारी का आनंद ले रहा हूं। ऋषभ पंत को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने के कारण अय्यर पांचवें नंबर पर उतरे लेकिन उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी क्रम चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में सभी को पता है कि बल्लेबाजी क्रम को लेकर लचीला होना पड़ेगा। सभी को हालात के अनुसार खेलना होगा।

लुईस और होप की शानदार पारियों से वेस्टइंडीज ने दूसरे एक दिवसीय में श्रीलंका को हराया

जमैका, (एजेंसी)। एविन लुईस और शाइ होप की शानदार बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को पांच विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासि कर ली है। लुइस और होप के बीच 192 रन की साझेदारी हुई। लुईस ने 103 जबकि होप ने 84 रन बनाये। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 8 विकेट पर 273 रन बनाए थे। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की शुरूआत अच्छी नहीं रही। उसका मध्यक्रम के बल्लेबाज रन नहीं बना पाये और कप्तान कीरोन पोलार्ड 46वें ओवर में आउट हो गए। इसके बाद निकोलस पूरन ने 38 गेंद में नाबाद 35 रन बनाकर आखिरी ओवर में टीम को जीत दिलाई। वेस्टइंडीज को आखिरी 18 गेंद में 31 रन चाहिए थे। फेबियन एलेन ने नुवान प्रदीप की पहली गेंद पर छक्का मारा पर अगली ही गेंद पर आउट हो गए। पूरन ने इसके बाद चौका लगाकर दबाव कम किया। आखिरी दो ओवर में वेस्टइंडीज को 13 रनों की जरुरत थी। श्रीलंकाई गेंदबाज दुष्मंता चामीरा ने 49वें ओवर में अच्छी गेंदबाजी की जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य नौ रन का रह गया। पूरन ने इसके बाद तेजी से रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। वहीं इससे पहले इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की शुरूआत अच्छी नहीं रही और उसने 50 रन के अंदर ही तीन विकेट खो दिए। इसके बाद दुष्मंता गुणतिलका ने 96 गेंद में 96 रन जबकि दिनेश चांदीमल ने 71 व विनांदु हसरंगा ने 47 रन बनाकर टीम को 273 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

ऋषभ ने ऑर्चर पर लगाया रिवर्स शॉट, पीटरसन और युवराज भी हुए हैरान

अहमदाबाद, (एजेंसी)। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 क्रिकेट मुकाबले में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारतीय टीम के केवल तीन बल्लेबाज ही इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना कर पाये। श्रेयस अय्यर ने ने जहां 67 रन बनाये। वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पंडया ने 19 और ऋषभ पंत ने 21 रन बनाए। ऋषभ पंत ने भले ही 21 रन ही बनाये पर अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने मैन ऑफ द मैच रहे रहस्यमयी तेज गेंदबाज जोफ्रा ऑर्चर पर एक ऐसा रिवर्स स्वीप शॉट मारा जिसे देखकर दिग्गज क्रिकेटरों के साथ ही पूर्व क्रिकेटर भी हैरान रह गए। भारतीय पारी के चौथे ओवर में ऑर्चर की गेंद पर ऋषभ ने पांचवीं गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेला जो हवा में होते हुए छह रनों के लिये मैदान से बाहर पहुंच गया। वहीं ऑर्चर भी ऋषभ के इस अनोखे रिवर्स स्वीप शॉट को देखकर हैरत में पड़ गये।

वहीं कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर भी ऋषभ के शॉट को देखकर काफी उत्साहित हो गये। इससे पहले टेस्ट सीरीज के दौरान भी ऋषभ ने इसी तरह से एक शॉट जेम्स एंडरसन की गेंद पर मारा था। अब एक बार फिर ऋषभ ने ऑर्चर पर ऐसा शॉट खेलकर दिखा दिया कि वह किसी भी गेंदबाज पर आक्रमण कर सकते हैं। युवराज ने ट्वीट किया औ लिखा, ये नई पीढ़ी है, जो बिल्कुल निडर है। रिवर्स या कौन सा शॉट, पता नहीं क्या कहूं इसको लेकिन एक तेज गेंदबाज को ऐसे मारने के लिए ऋषभ को सलाम है। ऐसे ही खेलते रहें। इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी ट्वीट कर इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज के इस शॉट की तारीफ की और इसे महानत शॉट करार दिया। पीटरसन ने ट्वीट में लिखा, ऋषभ ने क्रिकेट का अब तक का महानतम शॉट खेला। नई गेंद से गेंदबाजी कर कर रहे आर्चर की 90 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर पर इस प्रकार रिवर्स स्वीप से छक्का।

महिला फुटबॉल के विकास के लिए कोच शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रम शुरू

मुंबई, (एजेंसी)। विश्व फुटबॉल की शीर्ष संस्था (फीफा) की सहायता से अंडर17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 की स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) ने यहां महिला फुटबॉल के विकास के लिए कोच शिक्षा छात्रवृति योजना शुरू की है। इसके तहत महिला कोचों को तैयार किया जाएगा। इसमें ई-लाईसेंस कोर्स में उभरती हुई 21 कोचों को खेल के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तरह से प्रशिक्षित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार , यह कार्यक्रम कोच शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत को दशार्ता है जिसे महाराष्ट्र के अन्य जिलों में आगे बढ़ाया जाएगा। इसे महाराष्ट्र सरकार और पश्चिमी भारत फुटबॉल संघ (डब्ल्यूआईएफए) के साथ मिलकर पणे, ठाणे, नागपुर और कोल्हापुर में आयोजित किया जाएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत 2022 और एएफसी (एशियाई फुटबॉल परिसंघ) महिला एशियाई कप भारत 2022 के एलओसी की टूर्नामेंट निदेशक रोमा खन्ना ने कहा, यह हमारे लिए अहम है कि टूर्नामेंट की मेजबानी करने से स्थानीय समुदाय को लाभ हो सके और यह कार्यक्रम एक नई शुरूआत का संकेत है। उन्होंने कहा, जमीनी स्तर पर अधिक महिला कोचों की मौजूदगी से अधिक युवा लड़कियां और महिलाएं इस खेल से जुड़ेगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच मेमोल रॉकी ने कहा, पिछले वर्षों की तुलना में अब हर श्रेणी में अधिक महिला कोचों को देखना वास्तव में उत्साहजनक है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज वापसी के इरादे से उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम

लखनऊ, (एजेंसी)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले चौथे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में जीत के साथ ही फिर सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगी। इससे पहले तीसरे एकदिवसीय मैच में बेहतर प्रदर्शन के बाद भी भारतीय टीम को वर्षा बाधित मैच में डकवर्थ लुइस प्रणाली के तहत छह रनों से हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लिजेले ली ने 131 गेंद में 132 रन की नाबाद पारी खेलकर मैच का रुख पलट दिया था। भारतीय टीम इस मैच में एक समय बड़े स्कोर की ओर बढती दिख रही थी पर आखिरी पांच ओवर में ज्यादा रन नहीं बनाने के कारण वह पांच विकेट पर 248 रन ही बना सकी। कप्तान मिताली राज के अनुसार जीत के लिए हमें आखिरी दस ओवर में तेज खेलने वाले बल्लेबाज चाहिए। ऐसे में निचले क्रम के बल्लेबाजों से उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए हरमनप्रीत या दीप्त को यह जिम्मेदारी लेनी होगी।

दीप्ति अब तक अपेक्षा के अनुरुप नहीं खेल पायी हैं। जेमिमा रौद्रिगेज, पूनम राउत और कप्तान मिताली का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा नहीं है। स्मृति मंधाना ने अच्छा प्रदर्शन किया है पर रौद्रिगेज और राउत से उन्हें अब तक सहयोग नहीं मिल सका। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दस हजार रन पूरे करने वाली कप्तान मिताली ने दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी लय में हैं और उनपर टीम का भार रहेगा। राजेश्वरी गायकवाड़ ने पिछले मैच में अच्छी स्पिन गेंदबाजी की है और उनसे आगे भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। वहीं दूसरी ओर मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका की ओर से लिजेले ली अच्छी फार्म में हैं और उसने अब तक 219 रन बनाये हैं टीम को उससे इस मैच में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। गेंदबाजी की जिम्मेदारी शबनिम इस्माइल पर रहेगी। शबनिम ने अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के साथ ही विकेट भी लिए हैं।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं -

भारतः मिताली राज (कप्तान), स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, पूनम राउत, प्रिया पूनिया, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, डी हेमलता, दीप्ति शर्मा, सुषमा वर्मा, स्वेता वर्मा, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, झूलन गोस्वामी, मानसी जोशी, पूनम यादव, सी प्रत्यूषा और मोनिका पटेल।

दक्षिण अफ्रीकाः सुने लुस (कप्तान), अयाबोंगा खाका, शबनिम इस्माइल, लॉरा वोल्वार्ट, त्रिशा चेट्टी, सिनालो जाफ्ता, तस्मीन ब्रिट्ज, मारिजाने कैप, नोंडुमिसो सांगेज, लिजेल ली, एनेके बॉश, फाये ट्यूनिक्लिफ, नॉनकुलुलेको मलाबा, मिनगोन डु प्रीज, नेदिन डि क्लर्क, लारा गुडाल, टुमी सेखुखुने।

न्यूजीलैंड में इटली की रिना लूसा अमेरिका कप में टीम न्यूजीलैंड का मुकाबला करती हुई।

रोहित को आराम देने के विराट के फैसले से सहवाग हुए नाराज

नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टी20 में रोहित शर्मा को आराम देने के फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर रोहित फिट हैं तो उन्हें अंतिम ग्यारह में शामिल किया जाना चाहिये था। उनके बिना मैच देखने का मन नहीं करता। प्रशंसकों के साथ ही मैं भी रोहित की बल्लेबाजी देखने का इंतजार करना रहता हूं। पहले टी20 में श्रेयस अय्यर के अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी टिक नहीं पाया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने रोहित की जगह सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को मौका पर वह नाकाम रहे। धवन और लोकेश राहुल ने पारी की शुरूआत की पर दोनो ही रन बनाने में असफल रहे।

रोहित बाहर रखने पर सहवाग ने कहा, विराट ने कहा कि रोहित शुरूआती कुछ मैच नहीं खेलेंगे पर क्या भारत दूसरा मैच भी हार जाए तो यही रणनीति बनी रहेगी। हार से टीम पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. मैं अगर कप्तान होता तो जरूर अपनी अंतिम ग्यारह में रोहित को शामिल करता। रोहित अगर उपलब्ध हैं तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए। लोग भी रोहित जैसे खिलाड़ियों को देखने आते हैं। मैं भी रोहित का प्रशंसक हूं, अगर वह नहीं खेलते हैं तो मेरा टीवी ऑफ ही रहेगा। मैच देखने का मन नहीं करेगा।वहीं सहवाग ने कहा कि भारत अगर टी20 विश्वकप से पहले सलामी बल्लेबाजों का संयोजन तलाश रहा है तो उसे धवन, रोहित और राहुल तीनों को अंतिम 11 में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल वनडे में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, वह टी20 में चौथे नंबर पर उतर सकते हैं। इसके अलावा धवन को तीसरे नंबर भेजकर विराट खुद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं।

वॉन ने मुंबई इंडियंस को टीम इंडिया से बेहतर बताया, जाफर ने दिया करारा जवाब

मुम्बई, (एजेंसी)। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वान ने पहले टी20 में करारी हार के बाद टीम इंडिया का मजाक उड़ते हुए कहा है कि उससे तो अच्छी मुम्बई इंडियंस टीम है। इसपर पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने वान को करारा जवाब दिया है। इंग्लैंड ने पहले टी20 में भारतीय टीम से मिले लक्ष्य को आसानी से हासिल कर शानदार जीत दर्ज की है। इससे वान बेहद उत्साहित नजर आये हैं। उन्होंने यहां आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस टीम को भारतीय टीम से बेहतर बता दिया। वॉन की यह बात जाफर को सही नहीं लगी और उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा, सभी टीमें इतनी भाग्यशाली नहीं हैं कि वह 4 विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकें माइकल। बता दें कि यहां जाफर ने यह बात इसलिए बोली, क्योंकि इंग्लैंड टीम में चार ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो दूसरे देश के हैं। इसमें कप्तान इयोन मॉर्गन (आयरलैंड), जेसन रॉय (दक्षिण अफ्रीका), आदिल राशिद (पाकिस्तान) और जोफ्रा आर्चर (वेस्टइंडीज) विदेशी खिलाड़ी हैं। पहले टी20 में भारतीय टीम के बल्लेबाज उम्मीद के अनुरुप प्रदर्शन नहीं कर पाये। केवल श्रेयस अय्यर ही 67 रनों की पारी खेल पाये। अय्यर के अलावा ऋषभ पंत ने 21 रन बनाये। कप्तान विराट कोहली इस मैच में अपन खाता भी नहीं खोल पाये। इस प्रकार भारतीय टीम केवल 125 रनों का लक्ष्य ही इंग्लैंड को दे पाये। मेहमान टीम ने इस लक्ष्य को तय ओवरों से पहले ही हासिल कर लिया।

यूरोपा लीग में मिलान ने यूनाईटेड को ड्रॉ पर रोका

बर्लिन, (एजेंसी)। डिफेंडर साइमन जार के गोल से एसी मिलान ने मैनचेस्टर यूनाईटेड को यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम 16 के पहले चरण में 1-1 से बराबरी पर रोक दिया। जार ने इंजुरी टाइम में यह गोल किया। मिलान को 92वें मिनट में कार्नर मिला जिस पर जार ने गोल किया। इससे पहले स्थानापन्न खिलाड़ी अमाद डियालो नेके के गोली से यूनाइटेड ने यूरोपीय लीग में अपना पहला गोल करके 1-0 की बढ़त हासिल की।